RNI No. DELHIN/2012/48773 मासिक, विशेषांक 2020 वर्ष 9, अंक 3 ₹100

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

50 लोकप्रिय जिलाधिकारी

एशिया पोस्ट - फेम इंडिया सर्वे 2020

Shambhu's Foundation

(To creat Endless Happiness)

Address -
F Block - sector -50 , Noida -201304
(Delhi NCR)

Contact - +91-9911976808
Email ID - ss.fameindia@gmail.com
Website- www.shambhusfoundation.in

संपादकीय

FAME INDIA

फेम इंडिया

thefameindia.com

वर्ष 9, अंक 3, विशेषांक 2020

पैट्रॉन – ई. आर. महादेवन
मैनेजिंग डायरेक्टर / एडिटर-इन-चीफ – राजश्री
एडिटोरियल डायरेक्टर / सीईओ – यूएस सोंथालिया
चीफ आपरेटिंग आफिसर – शंकर सोंथालिया
मैनेजिंग एडिटर – श्वेता श्री
डायरेक्टर – के पी सोंथालिया
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर – राघवेश अस्थाना

रेजिडेंट एडिटर – धीरज कुमार
एसोसिएट एडिटर – भानु प्रकाश
एक्जीक्यूटिव एडिटर – मुकेश कुमार सिंह
आर्ट डायरेक्टर – स्वर्ण लता

एडिटोरियल टीम :-
शत्रुघ्न प्रसाद
श्वेता रश्मि
आनंद वर्मा
हेमंत सिंह
पार्थ श्रीवास्तव
संकेत सिंह
अमरदीप श्रीवास्तव
लता चौहान
मिथिलेश पाठक
अंजू भरमौरिया
रश्मि सिंह

मैनेजमेंट टीम :-
फाइनेंस आफिसर – हिमांशु नथानी
सेल्स मैनेजर – नीतू चौधरी
सर्कुलेशन मैनेजर – प्रवीण मिश्रा
एडमिन एक्जीक्यूटिव – सत्येंद्र सिंह
लीगल एडवाइजर – रश्मी भूषण

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स, ई-94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं ए-533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली से प्रकाशित, संपादक - राज श्री)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि।
762, ब्लाक-एफ 8, सेक्टर-50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. - +91-7004450124
ई मेल: info@thefameindia.com

RNI No. DELHIN/2012/48773

आवश्यक है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को संभालने वालों का प्रोत्साहन

भारतीय समाज में अक्सर कहा जाता है कि देश में पीएम, राज्य में सीएम और जिले में डीएम के पास ही जनता के लिये कुछ भी बेहतर कर पाने की ताकत होती है। यूं तो देश के विकास में सबकी भूमिका होती है, परन्तु देश व राज्य की पूरी मशीनरी विकास संबंधित योजनाओं का जो खाका तैयार करती है, उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की मुख्य जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की ही होती है और तभी बदलाव सही शक्ल भी लेता है। लोकप्रिय और सुघड़ जिलाधिकारी विकास योजनाओं का लाभ जन-जन को मिले यह सुनिश्चित करते हैं। चूंकि वे अपनी तैनाती के दौरान जिले की प्राकृतिक संपदाओं, कृषि, सड़क, बिजली, वित्त और मानव पूंजी से भली भांति परिचित हो चुके होते हैं, इसीलिए समस्याओं का निदान और विकास के नए पायदान गढ़ने के सूत्र उनके पास होते हैं। उन्हें पता होता है कि जिले में कितने संसाधन हैं और किस हिस्से की क्या जरूरत है, उसी के अनुरूप ये जिलाधिकारी योजनाएं बनाते हैं। इससे ही विकास को गति मिलती है।

किसी भी योजना की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आम लोगों से कितनी और किस तरह जुड़ी है तथा उसका लाभ जनता को किस तरह मिलने वाला है। वैसे तो जिलाधिकारी का विकास में सबसे अहम योगदान है, परन्तु आजकल ये आम धारणा बना दी गयी है कि ये कुछ खास काम नहीं करते। अक्सर इसे नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि सर्वांगीन विकास से लेकर किसी भी योजना के क्रियान्वयन तक में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है। 50 लोकप्रिय कलेक्टर के फेम इंडिया के इस अंक में हम जिलाधिकारियों के विकास और प्रगतिशीलता में दिये गये योगदान को सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक जिम्मेदार व सकारात्मक मीडिया होने के नाते फेम इंडिया ने इस बार देश निर्माण में अपनी बेहतर भूमिका निभा रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों व डिप्टी कमिश्नरों को श्रेय देने का निर्णय किया है।

वर्तमान में देश भर में 724 जिले हैं। फेम इंडिया मैगजीन ने एशिया पोस्ट सर्वे के साथ मिलकर विभिन्न स्रोतों, प्रबुद्ध लोगों की राय और ग्राउंड एवं मीडिया रिपोर्टों के आधार पर 50 लोकप्रिय जिलधिकारियों का चयन किया गया जो अपनी उत्कृष्टता के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमने सभी अधिकारियों को स्टेकहोल्ड सर्वे के आधार पर 50 कैटेगरियों में बांटा और हर कैटगरी से एक प्रमुख लोकप्रिय कलेक्टर को फेम इंडिया के अंक में कैटगरी और वरियता के आधार पर प्रकाशित किया गया है।

राजश्री

लोकप्रिय जिलाधिकारी

06 कुमार रवि 'उत्कृष्ट'
जिलाधिकारी- पटना

10 सुहास एल वाई 'कर्मयोद्धा'
जिलाधिकारी - नोएडा

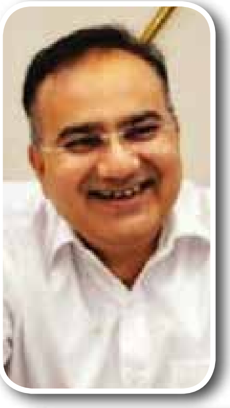

14 डॉ बृजमोहन मिश्रा 'योग्य'
जिलाधिकारी - दक्षिण दिल्ली

19 सुषमा चौहान 'क्षमतावान'
जिलाधिकारी - जम्मू

28 डॉ. त्यागराजन एस एम 'विलक्षण'
जिलाधिकारी - दरभंगा

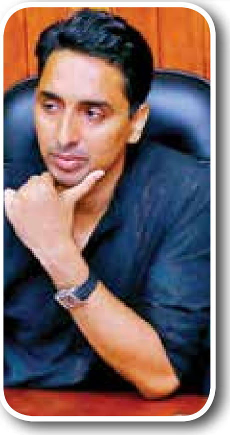

34 राई महिमापत राय 'जज्बा'
जिलाधिकारी - रांची

34 शशांक शुभंकर 'युवा'
जिलाधिकारी - समस्तीपुर

आगे कदम बढ़ाएं, सफलता अवश्य मिलेगी

देश भर के 724 जिलाधिकारियों में से 50 का चयन आसान नहीं रहा। मानदंड कई थे और हरेक विषय पर खरा उतरने वाले दर्जनों। इस सर्वे ने कम से कम एक बात तो स्पष्ट कर दी। आज देश का तकरीबन हर जिला प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हरेक जिलाधिकारी, चाहे वह किसी भी सर्विस के जरिये उस पद पर पहुंचा हो, पूरी लगन और निष्ठा से कार्यरत है। जिलाधिकारी बनना एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जो एक अधिकारी के जीवन में कुछ ही वर्षों के लिये आता है। इस दौरान सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और उदाहरण सेट करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे अधिकारी गिनती के है जिन्हें किसी कारणवश अपने कार्यों का सफल रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन उनकी भी भावनाएं स्पष्ट हैं। सर्वे में हमने पाया कई जिलाधिकारी अपने कार्यक्षेत्रों में प्रयोगात्मक कदम उठा रहे हैं जिनका परिणा। मीडिया अक्सर केवल सफल हो चुके प्रयोगों की ही चर्चा करता है, लेकिन हमें हर उस प्रयास की सराहना करनी चाहिये जो लोक कल्याण की नीयत से उठाये गये हैं।

सर्वे में कई ऐसे तथ्य सामने आये जिन्होंने प्रचलित मान्यताओं को बदल दिया। ऐसा माना जाता रहा था कि सिर्फ युवा अधिकारियों में उत्साह और जोश भरपूर होता है और वे उम्रदराज अधिकारियों से अपेक्षाकृत ज्यादा कार्य करते हैं। राज्य सेवा से आये कई जिलाधिकारियों ने इस धारणा को भी तोड़ दिया और अपने अनुभव व समझदारी को उत्साह के साथ जोड़कर आश्चर्यजनक परिणाम दिया है। हमने शानदार गवर्नेंस, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, गंभीरता और व्यवहार कुशलता आदि दस मानदंडों पर सभी 724 जिलों के कलेक्टरों को परखा। संख्या अधिक थी इसलिये हमने 50 श्रेणियों में उन्हें बांट कर स्टेकहोल्ड, आधिकारिक रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अंक बिठाये। इस सर्वे को निष्पक्ष और एरर फ्री रखने के लिए इसे कई स्तरों तक गुप्त रखा गया और सभी चयनित अधिकारियों को परिणाम आने के बाद ही सूचित किया गया।

इक्का-दुक्का जिले ऐसे भी मिले जहां के मुखिया का या तो सर्वे के दौरान या उसके कुछ सप्ताह पहले ही तबादला हो गया। उनमें से कुछ अधिकारियों के पिछले उल्लेखनीय परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें शामिल किया गया। सबसे संतोषजनक बात ये रही कि अधिकतर श्रेणियों में अव्वल आये जिलाधिकारी अपने प्रतियोगी से कुछ ही अंकों के फासले पर रहे। यानी द्वितीय या तृतीय, चतुर्थ आने वाले अधिकारी भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उन्हें लिस्ट में न आने पर निराश नहीं होना चाहिये। हम आशा करते हैं कि वे अगले साल तक उन मानदंडों को समझेंगे और उनपर अव्वल आने का प्रयत्न करेंगे। विकासवादी सोच के अधिकारी चाहे जिस पद पर रहें, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वे निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्हें सम्मान अवश्य मिलेगा।

हार्दिक शुभकामनाएं
जय हिंद
टीम फेम इंडिया - एशिया पोस्ट
thefameindia.com

उत्कृष्ट

उत्कृष्ट कार्यशैली के बेहतरीन अधिकारी

कुमार रवि

पटना के डीएम कुमार रवि अपने मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और प्रशासनिक जवाबदेही के निर्वहण के लिए जाने जाते है। बिहारशरीफ के एक सामान्य परिवार में जन्मे कुमार रवि के पिता बर्तन के व्यवसायी है और माता गृहणी थी। कुमार रवि की पत्नी कुशल गृहणी है, जिलाधिकारी के पद पर जनता की बेहतरी के लिए वे हमेशा अपने पति के मनोबल को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुमार रवि की शुरुआती पढ़ाई बिहार शरीफ के स्कूल में हुई, फिर तत्कालीन समय के प्रतिष्ठित नेतरहाट स्कूल में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उनका एडमिशन हुआ।

कुमार रवि ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर वीएलएसआई इंजीनियर काम किया। उन्होंने 2002 में प्राईवेट सेक्टर छोड़कर सिविल सेवा में जाने का निश्चय किया। यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार 2003 में उन्हें इंडियन रेवन्यू सर्विस मिला। वर्ष 2005 में कुमार रवि आईएएस की परीक्षा में पूरे देश में 10वां स्थान लाने में सफल रहे। कुमार रवि ने बेतिया में असिस्टेंट कलेक्टर के रुप में ज्वाइन किया। वे मुजफ्फरपुर में एसडीओ के तौर पर भी रहे। मई 2009 में सुपौल के जिलाधिकारी बनाये गये। जहाँ उन्होंने बाढ़ नियंत्रण और एन एच 57 फोरलेन के काम में तेज़ी लाने के साथ ही दो सौ से ज्यादा स्कूलों के लिए जमीन मुहैया का काम सफलतापूर्वक करवाया। जनवरी 2013 में कुमार रवि को दरभंगा का जिलाधिकारी बनाया गया। जहाँ उनका बाढ़ नियंत्रण और सांप्रदायिक सौहार्द को जिला में कायम रखने का प्रयास बेहद सराहनीय रहा। कुमार रवि को दिसंबर 2015 में गया का जिलाधिकारी बनाया गया। इनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने 2016-17 में पितृपक्ष मेला, 2017 में दलाई लामा की अगुआयी में होने वाली काल चक्र पूजा बेहद सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया।

कुमार रवि की गिनती बेहद काबिल और अनुभवी जिलाधिकारियों में होती है। वे 1 जनवरी 2018 से पटना के जिलाधिकारी हैं। यहाँ उन्होंने जिले में बेहतर कार्य संस्कृति स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाने से लेकर जिले में स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की कोशिश में इनकी उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की जाती है। कई कठिन परिस्थितियों का कुमार रवि ने जवाबदेह तरीके से निराकरण कर अपनी पहचान लोकप्रिय जिलाधिकारी के तौर पर स्थापित की है। कोरोना संकट में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी पहली प्राथमिकता रही है। वे लोगों की जागरूकता के लिए विभिन्न क्षेत्र में जा कर प्रेरित करते है। कुमार रवि को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनेक अवाड्र्स और सम्मान प्राप्त है। जिसमें 2019 में वूमन एंड चाइल्ड डेवल्पमेंट मिनिस्ट्री की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अवार्ड, 2018 में बेस्ट डीएम का अवार्ड, लोकसभा चुनाव 2019 में बेस्ट इलेक्ट्रोरल अवार्ड आदि प्रमुख हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि 'उत्कृष्ट' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

विशिष्ट

प्रशासनिक विशिष्टता की रिकॉर्ड होल्डर

शालिनी अग्रवाल

जयपुर में 28 अक्टूबर 1980 को राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी शिव कुमार अग्रवाल के घर शालिनी का जन्म हुआ। जयपुर से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद पिता से प्रेरणा लेकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया। 2005 बैच में उन्हें यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी मिली और गुजरात कैडर मिला। जून 2006 में शालिनी अग्रवाल दाहोद की असिस्टेंट कलेक्टर फिर गोधरा की एसडीएम बनायी गयीं। उन्होंने गोधरा में ही जिला विकास अधिकारी का पदभार भी संभाला। शालिनी अग्रवाल 2007 से 2012 तक तापी, नडियाद आदि जिलों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहीं। सभी पोस्टिंग में उन्होंने अपनी पहचान दायित्वों को कुशलता से निभाने वाली अधिकारी की बनायी।

वर्ष 2012 में शालिनी अग्रवाल की पोस्टिंग अरावली कलेक्टर के पद पर की गयी, जहाँ उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक अलग पहचान कायम की। जून 2017 में उन्होंने तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये। शालिनी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक ही जिले में 1500 गर्भवती महिलाओं का एक शिविर लगाया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने 3000 छात्रों को एकत्रित कर विश्व का सबसे बड़ा लिफाफा मोजैक बनवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बनावा कर तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन-तीन विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया। अप्रैल 2018 में उन्हें वडोदरा का जिलाधिकारी बनाया गया, जहाँ उन्होंने विकास की नयी इबारत लिखी। अगस्त 2019 में वड़ोदरा में भारी बारिश और बाढ़ से जल जमाव होने की स्थिति को उन्होने प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ निभाया और लोगों को जिला प्रशासन से हर संभव मदद मिली। उनके नेतृत्व में मतदाता जागरुकता अभियान की वजह से 2019 के संसदीय चुनावों में वड़ोदरा ने राज्य के मेट्रोपोलिटन शहरों में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बनाया। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए शालिनी अग्रवाल को राज्य-स्तरीय 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चुनाव प्रक्रिया में गुजरात की श्रेष्ठतम डीईओ और कलेक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया। कोरोना संकट के समय में वे हर तहसील और जिले के तमाम अधिकारियों से संपर्क में हैं और सरकार की गाइडलाइंस पर सख्ती से काम कर रही हैं।

अपने नाम के अनुरूप ही शालीनता, दृढ़निश्चय और वचनबद्धता के लिए पहचानी जाने वाली प्रतिभा सम्पन्न शालिनी अग्रवाल जनता की सेवा को सर्वोपरि मानती हैं। यही वजह है कि वड़ोदरा के लोगों को किसी भी आपदा या मुसीबत में एक जिलाधिकारी से अधिक पारिवारिक सदस्य की तरह मदद की। हर जगह रिकॉर्ड बनाने वाली इन अधिकारी की लोकप्रियता भी अपने-आप में एक रिकॉर्ड है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर वडोदरा के जिलाधिकारी शालिनी अग्रवाल 'विशिष्ट' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कर्त्तव्यनिष्ठ

कर्तव्यनिष्ठा से लोकप्रिय छवि बनायी है

कौशल राज शर्मा

जन-जन की आस्था से जुड़े और देश के सबसे हाईप्रोफाइल जिले के तौर पर मशहूर पौराणिक नगरी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा विनम्र स्वभाव के मृदुभाषी किन्तु सख्त अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र के कारण वीआईपी कहे जाने वाले इस जिले के कर्ता-धर्ता सामाजिक ताने-बाने का ख्याल रखने के साथ ही वे विकासवादी सोच भी रखते हैं। कौशल राज शर्मा का जन्म हरियाणा के भिवानी में एक सामान्य परिवार में हुआ। मेधावी कौशल राज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई में भी स्कॉलरशिप प्राप्त किया, वे नवोदय विद्यालय से 12वीं की परीक्षा अव्वल नंबर से पास हुए।

उन्होंने रोहतक से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। बेहद होनहार कौशल राज शर्मा ने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया। उन्होंने सिविल सर्विसेज को समाज सेवा का सबसे बेहतरीन माध्यम माना और इसकी तैयारी में जुट गये। कौशल राज शर्मा का चयन 2006 बैच में आईएएस के लिए हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। बतौर असिस्टेंट कलेक्टर कौशल राज बरेली में प्रोबेशनर रहे, जुलाई 2010 में कौशल राज शर्मा पीलीभीत के कलेक्टर बनाये गये। इसके बाद उन्हें लखनऊ में लैंड इक्विजिशन और राजस्व बोर्ड की जिम्मेदारी दी गयी। वे 2013 में मुजफ्फनगर और 2015 में प्रयागराज के डीएम भी रहे हैं। कौशल राज शर्मा को 2015 सितंबर में कानपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मामले को अपनी प्रशासनिक कौशल से सफलता पूर्वक हल किया। कानपुर में विकास और स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया।

कानपुर से उनका ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र की योजना में समनव्य का उत्कृष्ट नमूना पेश किया। कौशल राज शर्मा ने लखनऊ ने लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, राजधानी की स्वच्छता और सड़क पर विशेष ध्यान दिया गया। लोकसभा चुनाव भी उन्होंने शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में कामयाबी हासिल की। नवंबर 2019 में उनकी प्रशासनिक उत्कृष्टता को देखते हुए वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से इस पर विश्व भर की मीडिया का ध्यान लगा रहता है और प्रदेश के साथ-साथ केंद्र सरकार का भी, अतः इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंचते ही उन्होंने वाराणसी को मॉडल जिला बनाने और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, पर्यटन, स्वच्छता, कॉरीडोर और फ्लाईओवर को प्राथमिकता में रखा। कोरोना काल में भी वे बेहद सजग जिलाधिकारी की भूमिका में हैं। जिले में उनके नेतृत्व में जागरूकता, केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइंस का पालन, क्वारंटाइन सेंटर की सुव्यवस्था और संक्रमितों के इलाज की खास व्यवस्था की गयी।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा 'कर्त्तव्यनिष्ठ' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

हौसलामंद

हौसलों की ऊँची उड़ान भरते आईएएस

प्रदीप कुमार अग्रवाल

कहते हैं हौसलों से ही उड़ान होती है, और इसी हौसले के साथ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव किरौली के प्रदीप इंफोसिस की नौकरी को त्याग, पारदर्शिता से जनकल्याणकारी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य लेकर प्रशासनिक सेवा में उतर गये। 2006 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस प्रदीप कुमार अग्रवाल बुलंद हौसला रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रदीप कुमार अग्रवाल का जन्म 21 नवंबर 1979 को आगरा के किरौली में हुआ।

गांधी समरला किसान इंटर कॉलेज किरौली, आगरा से स्कूलिंग करने के बाद प्रदीप अग्रवाल का चयन आईआईटी कानपुर के लिए हुआ। वहाँ से उन्होंने मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग करने के बाद बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने देश की सबसे प्रसिद्ध कंपनी इंफोसिस ज्वाइन की। दो साल वहाँ कार्यरत रहने के बाद प्रदीप कुमार अग्रवाल ने प्रशासनिक सेवा में आने का मन बनाया और यूपीएससी की परीक्षा पास कर 2006 बैच के पंजाब कैडर में आईएएस बने।

प्रदीप कुमार अग्रवाल की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर होशियारपुर और फिर अगली नियुक्ति 2008 में संगरूर के एडीएम के पद पर हुई। 2009 अक्टूबर तक उन्होंने संगरूर, फाजिल्का और बलाचौर भूराजस्व के क्षेत्र में काफी काम किया। इसके बाद उन्हें लुधियाना का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, जहाँ उन्हें भूराजस्व के साथ नगर निगम और शहरी विकास डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी समय-समय पर दी गयी। इस दौरान उन्होंने लुधियाना नगर निगम को बदहाली से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वहाँ के बाद वे रोपड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर बनाये गये, जहाँ उन्होंने उत्कृष्ट कार्यशैली का प्रदर्शन करते हुए जिले के विकास के लिए निर्भिकता से बड़े निर्णय लिये। मिड डे मील का बेहतर डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर धांधली करने वालों पर नकेल कसी। पहली बार जिले में ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया। उन्होंने रोपड़ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया। वर्ष 2017 में प्रदीप अग्रवाल को लुधियाना का उपायुक्त बनाया गया। उनकी अगुआई में लुधियाना को कृषि में देश के सर्वश्रेष्ठ जिले और उद्योगों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला, वहीं जल संरक्षण के क्षेत्र में भी ये पूरे उत्तर भारत में तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2019 में प्रदीप कुमार अग्रवाल को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट डीईओ का अवार्ड भी मिल चुका है। प्रदीप कुमार अग्रवाल के कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के कार्यों को बेहद सराहना मिली। बहरहाल, तीन वर्षों से लुधियाना जिले को नित नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद प्रदीप कुमार अग्रवाल को इसी महीने जून 2020 में ट्रांसफर कर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट के साथ डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एडिशनल जिम्मा दिया गया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर लुधियाना के जिलाधिकारी प्रदीप कुमार अग्रवाल 'हौसलामंद' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कर्मयोद्धा

चुनौतियों को पार पाने का हुनर जानते हैं कर्मयोद्धा

सुहास एल. वाई.

अनुशासित और चुनौतियों से मुकाबला का हुनर जानने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रहे, यश भारती सम्मान प्राप्त आईएएस सुहास लालिनाकेरे यथिराज (एल. वाई.) वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी हैं। कोविड 19 वैश्विक महामारी के समय हाई प्रोफाइल शहर नोएडा में जब स्थितियां बेकाबू होने लगीं तब सुहास एल. वाई. की नियुक्ति उनके कुशल प्रशासनिक कौशल को देखते हुए की गयी।

कर्नाटक के रहने वाले सुहास एल. वाई. की शुरुआती पढ़ाई शिमोगा में हुई। उन्होंने एनआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया और 2007 में सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल की। उनकी पत्नी भी राज्य प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं। सुहास एल. वाई.की पहली पोस्टिंग बतौर असिस्टेंट कलेक्टर आगरा में हुई। जुलाई 2009 में वे आजमगढ़ के ज्वांइट मजिस्ट्रेट बनाये गये। इसके बाद वे मथुरा में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बने। वहाँ के बाद वे महाराजगंज, सोनभद्र और हाथरस आदि जिलों में भी पोस्टेड रहे ।इसके बाद वे करीब तीन साल तक जौनपुर के डीएम रहे। इस दौरान उन्होंने जौनपुर में विकास कार्यों को नया आयाम दिया। उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें आजमगढ़ जिले की कमान सौंपी गयी जो अपनी अव्यवस्थाओं और पिछड़ेपन की वजह से बदनाम था। अपनी सभी पोस्टिंग में उन्होंने गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और पाजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल कायम की। आजमगढ़ में उन्होंने लोगों में खेल भावना को भी आगे बढ़ाया।

सुहास एलवाई शुरू से एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उनके नाम डेढ़ दर्जन अंतरराष्ट्रीय मैडल्स हैं। पैरा बैडमिंटन में उन्हे विश्व में नंबर -2 की रैंकिंग प्राप्त है। उन्होंने शटलर के रूप में 2016 में बीजिंग एशियन चैंपियनशिप में लोअर स्टैंडिंग-4 में गोल्ड जीत कर देश का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि के लिए सुहास एलवाई को प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। उनकी जवाबदेह कार्यशैली और अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता के कारण महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गयी। कुंभ को सुव्यवस्थित और शानदार तरीके से आयोजित कराने के लिए उनके कार्यों की जमकर तारीफ हुई। उनकी प्रशासनिक उत्कृष्टता को देखते हुए वर्ष 2019 में उन्हें स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अधिकारियों में माना जाता है। अप्रैल 2020 में नोएडा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू करने के लिए उन्हें सीएम ने खुद नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर का डीएम बनाया। नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कल्चर और तमाम मीडिया व आईटी हब होने की वजह से यह शहर बेहद हाई प्रोफाइल माना जाता है। सुहास एलवाई जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयासों को मजबूती से कर रहे हैं। कोरोना काल में उनके कार्यों को एक योद्धा की तरह देखा जा रहा है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. 'कर्मयोद्धा' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

बाजीगर

हार को जीत में बदलने वाले बाजीगर

राजेंद्र भट्ट

उत्कृष्ट कार्यक्षमता और चुनौती को सुलझाने की कारीगरी, कोविड 19 की पहेली सुलझा कर देश भर में चर्चित हुए भीलवाड़ा मॉडल के प्रणेता राजेंद्र भट्ट 2007 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी सोच दूरदर्शी मानी जाती है और किसी भी फैसले को कार्यरूप देने में उनकी कोई तुलना नहीं है।

राजेंद्र भट्ट का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। वे इकोनॉमिक्स से एमए हैं और आरपीएस अधिकारी रहे चुके हैं। 2007 बैच में उन्हे राजस्थान कैडर में आईएएस पद पर प्रोन्नत किया गया। आईएएस राजेंद्र भट्ट की पोस्टिंग कॉपरेटिव सोसायटी, उदयपुर में एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर हुई। इस दौरान उन्होंने कॉपरेटिव सिस्टम में बेहतरीन सुधार कार्य किया। मई 2017 को उन्हें डूंगरपुर का कलेक्टर बनाया गया। उन्होंने यहां जैविक खेती के साथ ही कम्पोस्ट युनिट के निर्माण को भी बढावा दिया, ताकि इसका सीधे तौर पर फायदा किसानों को मिल सके। इसके अलावे उन्होंने डूंगरपुर में रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन आदि को सुधारने पर भी विशेष कार्य किये। डूंगरपुर में उनकी कार्यशैली और शानदार गवर्नेंस को सरहानीय माना जाता है।

दिसंबर 2018 में राजेंद्र भट्ट को भीलवाड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया। कपड़ों की मशहूर औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में भी उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता मिशन, सड़क निर्माण और रोजगार के माध्यमों को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया। एक वाक्या तो इस दौरान तब हुआ जब वे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में गंदगी देख खुद झाड़ू लेकर अस्पताल की सफाई में उतर गये। यह जहाँ एक ओर उनकी काम के प्रति निष्ठा को दर्शाता है वहीं जिले में लोगों के बीच साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर एक बड़ा मैसेज गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल के सभी मेडिकल उपकरणों को दुरुस्त करवाने के साथ ही मरीजों की जांच अस्पताल से बाहर कराने पर रोक लगवायी। राजेन्द्र भट्ट के नेतृत्व में भीलवाड़ा एक बेहतर जिले में शुमार हुआ। इसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बादल भीलवाड़ा में भी तेजी से गहराने लगे। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन बिगड़ी हुई परिस्थिति को कलेक्टर ने अपनी सूझ-बूझ से पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद उनके काम की तारीफ 'भीलवाड़ा मॉडल' के तौर पर देश भर में हुई। राजेंद्र भट्ट ने इस जानलेवा बीमारी की चेन को तोड़ने का काम किया। उन्होंने जिले में हॉटस्पॉट की मैंपिंग, घर-घर जाकर स्क्रीनिंग, कॉनटेक्ट ट्रेसिंग, क्वारेंटाइन और आइशोलेसन इत्यादि की उच्च स्तरीय व्यवस्था करवायी। सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के साथ-साथ लोगों को घर में ही जरूरत का सामान उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत सप्लाई सिस्टम बनवाया। उनके स्ट्रेटेजी और मॉडल की चर्चा हर क्षेत्र में हो रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर भीलवाड़ा के जिलाधिकारी राजेंद्र भट्ट 'बाजीगर' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

अग्रदूत
★★★★★

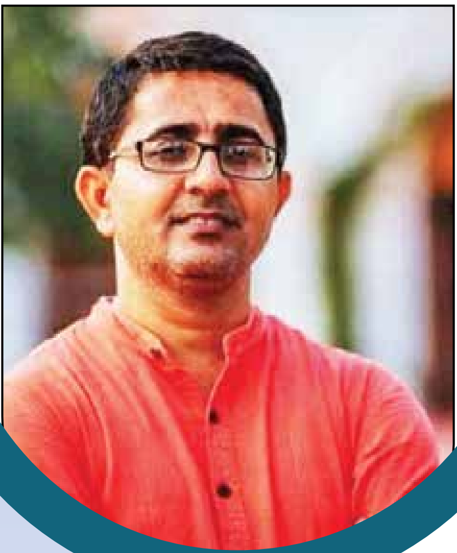

सुशासन और विकास के अग्रदूत हैं बलवंत सिंह

अनुशासित, निर्भीक और ईमानदार छवि वाले लक्ष्य को पाने लिए निरंतर प्रयास करने वाले 2007 बैच के बलवंत सिंह ओडिशा के पुरी जिले के कलेक्टर हैं। अपने कार्य-कलापों से उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच एक खास जगह बना ली है। बलवंत सिंह का जन्म राजस्थान में बाड़मेर के कालेवा गांव में एक बेहद सामान्य परिवार में 15 जुलाई 1977 को हुआ। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक पढ़ाई बाड़मेर के बालोतरा से की। एमडी सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर से बलवंत सिंह ने स्नातक की डिग्री हासिल की।

वर्ष 2000 में उनका चयन को-ऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर हुआ, लेकिन वे सफलता के बाद रुके नहीं क्योंकि उनका लक्ष्य आईएएस बनना था। वर्ष 2005 में उन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 5 वीं रैंक हासिल की, लेकिन सिविल सर्विसेज का प्रयास जारी रखा। वर्ष 2007 में 35 वीं रैंक के साथ आईएएस में सेलेक्ट हुए और ओडिशा कैडर मिला। बलवंत सिंह सर्वप्रथम बालीगुडा में एसडीएम बनाये गये। फिर उन्हें मलकानगिरि जिले में डिस्ट्रिक्ट रूलर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बाद में जिले का कलेक्टर बनाया गया। वहां उन्होंने ट्राइबल एजुकेशन के कार्यों को बेहद सराहनीय तरीके से अंजाम दिया। इसके बाद वे केंदुझार के जिला कलेक्टर बनाये गये। मई 2013 में उन्हें संभलपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। वहां उन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त करने के साथ ही रोड, ड्रेनेज, स्वच्छता आदि पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और टेक्निकल एजुकेशन बनाया गया, उन्होंने अपनी सभी पोस्टिंग में शानदार गवर्नेंस, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता से बेहतरीन काम किया।

बलवंत सिंह की जिम्मेदार कार्यशैली को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें फेनी तूफान से लगभग तबाह हो चुकी धार्मिक नगरी पुरी का कलेक्टर बनाया। मई 2019 में पद भार संभालते ही उन्होंने बाधित हुई सड़कों और टेलीकॉम सेवा को तुरंत दोबारा बहाल करवाने के कार्य किये। इस दौरान उन्होंने लोगों की सेवा के अपने फर्ज में हर जोखिम उठाने के साथ बड़ी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता से प्रशासनिक दायित्व को निभाया, जिससे उनपर सरकार और जनता का विश्वास भी कायम हुआ। उन्होंने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया। कोरोना को देखते हुए जिलाधिकारी बलवंत सिंह ने पुरी जिले में गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करवाया, साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर कोर्ट के फैसले को देखते हुए व्यापक तैयारी की, जिससे भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की हर रस्म अनुशासित तरीके से पूरी हो सकी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सीमित संख्या में भगवान के दर्शन आदि को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रशासन को फ्रंट से लीड किया।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पुरी के जिलाधिकारी बलवंत सिंह 'अग्रदूत' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

प्रभावशाली

दूरदर्शिता से अपनी पहचान बना चुके के. विजयेंद्र पांडियन

वैसे तो तमाम जिलाधिकारी अपनी प्रशासनिक जवावदेही के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ विशेष प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे ही हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन, जो अपनी विशेष कार्यशैली के लिये जाने जाते हैं। उनके कार्यों से सूबे के मुख्यमंत्री इतने प्रभावित हैं कि इन्हें अपने जिले की कमान सौंप रखी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है और यही कारण है कि वे जिले की आवाम के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

18 जुलाई 1981 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे के विजयेंद्र पांडियन ने बीबीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। वे वर्ष 2008 में आईएएस की सेवा में चुने गये। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शक्ति रत्ना मदुरै में रहती हैं और वे के. विजयेंद्र पांडियन की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानी जाती हैं। के विजयेंद्र पांडियन की पहली पोस्टिंग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इटावा के पद पर हुई। करीब 11 महीने बाद उनका ट्रांसफर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चंदौली हो गया। अपनी दूरदर्शिता और बेहतर कार्यों के बदौलत अपनी पहचान बना चुके के.विजयेंद्र पांडियन बलिया, कानपुर के जिला कलेक्टर रहने के बाद वर्ष 2013 में बलरामपुर के डीएम बनाये गये। लगभग एक साल में उन्होंने जो प्रसाशनिक सुधार किये उनसे इनकी गिनती उम्दा प्रशासकों में होने लगी। इसके बाद उन्हें कई अहम पदों की जिम्मेदारियां मिलीं। जिनमें स्पेशल सेक्रेटरी यूपी पंचायती राज, एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन डिपार्टमेंट यूपी, एडिशनल एमडी यूपीएसआरटीसी, डीएम एंड कलेक्टर कासगंज, मैनेजिंग डायरेक्टर एस सी फाइनेंस डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन अहम हैं।

मई 2017 में इन्हें कानपुर डेवल्पमेंट ऑथिरिटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया। कानपुर में उन्होंने विकास के कई कार्य करवाये। मार्च 2018 में के. विजयेंद्र पांडियन गोरखपुर के डीएम बनाये गये। उन्होंने जन समस्याओं को तेजी से निपटाया और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के कार्यों में तेजी लायीं। दरअसल हमेशा उनका फोकस केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में रहता है। कोरोना संकट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके काम की जमकर तारीफ हो रही है। वे कोरोना महामारी पर मदुरै में रहने वाली अपनी चिकित्सक पत्नी शक्ति रत्ना से भी राय लेते रहे और इसे गोरखपुर वासियों की बेहतर सेहत लिए इस्तेमाल में लाते रहे। बतौर जिलाधिकारी उन्होंने अपने जिले की परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लिया। लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर के होम डिलीवरी मॉडल की खूब चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने होम डिलीवरी मॉडल के प्रजेंटेशन को मंगवाया।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर गोरखपुर के जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन 'प्रभावशाली' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

योग्य

गरीबों की सेवा के लिए आईएएस बने
डॉ. बृज मोहन मिश्रा

चाहत हो तो सफलता खुद-ब-खुद चल कर आती है। जी हां ये बात साउथ दिल्ली के जिला उपायुक्त डॉक्टर बीएम मिश्रा पर सौ फीसदी सही बैठती है। दरअसल बृजमोहन मिश्रा एक किसान परिवार से आते हैं उनका जन्म यूपी के मऊ में 1 दिसंबर 1979 को हुआ। वे 6 भाई-बहन है। इनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी से बॉयोलॉजी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ से एमबीबीएस की पढ़ाई की।

सामान्य परिवार से होने के कारण बृजमोहन ने लोगो के रोजमर्रा के संघर्ष को काफी नजदीक से एहसास किया था लिहाजा उनके मन में जरूरतमंदों की कठिनाई को दूर करने की गजब की ललक है। इस मकसद से उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया। 2008 बैच में बृजमोहन मिश्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। उन्हें यूटी कैडर मिला। डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा 2010 से 2012 तक दिल्ली में एसडीएम रहे। फिर ईस्ट दिल्ली के डिप्टी कमीशनर बनाए गए। वे जहाँ भी रहे उन्होंने गरीबों की सेवा करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा की कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें कई अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई। अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान डॉ बीएम मिश्रा ने अपने प्रशासनिक दायित्वों का बेहतर निर्वहण किया। वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर द्वारा उनकी कार्यशैली और विकास कार्यों और "उत्कृष्ट जन सेवा" के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वे 12 सितंबर 2018 को एडिशनल कमीशनर, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन बनाए गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने स्वच्छता से जुड़े कई कार्य आम लोगों की भलाई के लिए किया।

13 जून 2019 को डॉ मिश्रा को साउथ दिल्ली का डिप्टी कमीश्नर बनाया गया। उन्होंने साउथ दिल्ली में विकास के तमाम गतिविधियों को बड़े ही सहज तरीके से आगे बढ़ाया। बतौर डीसी जनमानस के लिए उपलब्धता, सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया और बेहतर तालमेल के साथ विकास के लिए डॉ मिश्रा की चर्चा की जाती है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के दस्तक देते ही खुद डॉक्टर रहे बृज मोहन मिश्रा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रशासनिक अनुभव से लोगों की सेवा की। जिससे साउथ दिल्ली का इलाका दिल्ली के अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित रहा। उन्हें हाल ही में कोविड के खिलाफ सर्वोत्तम रिस्पॉंस करने वाले जिलाधिकारी के तौर पर स्कोच गोल्ड अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुंओं पर किये गए आंकलन के आधार पर दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा 'योग्य' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

बेहतर ★★★★★

समाज के लिए बेहतर करने को उत्सुक
नवल किशोर राम

नवल किशोर राम का जन्म 15 सितंबर 1977 को बिहार के मोतिहारी में एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रैजुएशन करने के बाद इतिहास में मास्टर्स डिग्री हासिल की। आईएएस बनने का लक्ष्य उन्होंने बचपन में निर्धारित कर लिया था। 2008 बैच में वे सिविल सर्विस में सफल रहे और उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला। निर्भीक और चुनौतियों से मुकाबला करने में निपुण नवल किशोर का करीयर भी शानदार रहा है। बुलंद हौसले के साथ सही फैसला लेने वाले नवल किशोर राम की पहली पोस्टिंग नांदेड़ के किनवात नगर परिषद में सीईओ के तौर पर हुई। वहाँ एक वाक्ये में अतिक्रमणकारियों ने उन पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, परन्तु उन्होंने हौसला नही खोया और निडरता से कार्रवाई करवायी। उन्हें महाराष्ट्र के कई जिलों में अहम जिम्मेदारियां मिलीं जिनमें यवतमाल में जिला परिषद के सीईओ का पद भी शामिल था। नवंबर 2013 में वे बीड जिले के कलेक्टर बनाये गये। वहां उन्होंने दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

जिले में सूखे से निपटने और सिंचाई से संबंधित कई प्रभावकारी योजनाएं चलायीं। अप्रैल 2017 में उन्हें औरंगाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया जहां उन्होंने कचरे के निस्तारण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष कार्य किया। औरंगाबाद में कचरे से कम्पोस्ट बनवाने का कार्य भी शुरू करवाया, जिससे स्वच्छता के साथ कृषि को भी मदद मिलने लगी। अप्रैल 2018 में नवल किशोर राम को पुणे का डीएम बनाया गया। बतौर कलेक्टर उन्होंने महाराष्ट्र की सांकृतिक राजधानी स्मार्ट सिटी पुणे की व्यवस्था को जोरदार तरीके से सुधारने के लिए ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, लॉ एंड आर्डर, स्वच्छता व सर्वांगीन विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने कोरोना संकट में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मजबूत निर्णय लिये जिससे पुणे मॉडल की चर्चा चारों तरफ हुई। एजुकेशन हब पुणे से दूसरे राज्यों के छात्रों की घर वापसी के काम को लॉकडाउन में उन्होंने खुद अपनी देख रेख में करवाया। ऐसे में बतौर बेहतर जिलाधिकारी नवल किशोर राम के प्रशासनिक कौशल की सराहना हो रही है।

FAME INDIA

आशावादी और गंभीर स्वभाव, मेहनत से इस मुकाम को हासिल करने वाले नवल किशोर राम की प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। 2008 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी नवल किशोर राम वर्तमान में पुणे के कलेक्टर हैं। प्रदेश में उनकी गिनती वैसे दूरदर्शी अफसरों में होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम 'बेहतर' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

शक्ति

शानदार गवर्नेंस और उत्कृष्ट सोच की शक्ति स्वरूप हैं

मुक्ता आर्या

लक्ष्य के प्रति उच्च मनोबल, बुनियादी चीजों को बेहतर तरीके से समझना और मेहनत से सफलता प्राप्त करने में यकीन रखने वाली मुक्ता आर्या 2008 बैच की आईएएस हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की कलेक्टर हैं। उन्होंने सदैव अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए प्रशासन को सही करने में अहम योगदान दिया और लोगों के बीच लोकप्रियता अर्जित की। दिल्ली में पली-बढ़ीं मुक्ता का परिवार मूल रुप से राजस्थान का है। उनके पिता भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं।

मुक्ता आर्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एमए भी किया। उन्होंने पॉन्डिचेरी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया है। 2008 बैच में मुक्ता आर्या को यूपीएससी में कामयाबी मिली। 48वीं रैंकिंग के साथ उन्हें वेस्ट बंगाल कैडर मिला। मुक्ता आर्या को पहली पोस्टिंग में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। 2010 में उन्हें मुर्शिदाबाद और उसके बाद सेरामपोर में एसडीओ बनाया गया। मई 2012 में मुक्ता आर्या का तबादला हुबली जिले में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ। इसके बाद उन्हें कुछ महीनों के लिये कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार बनाया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के स्वरोजगार के लिये कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का निर्माण करवाया जिनमें से उत्तर दिनाजपुर जिले का 'ऐलो' खासा चर्चित रहा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी काफी सराहना भी की।

इसके बाद मुक्ता आर्या को जलपाईगुड़ी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया जहां उन्होंने ग्रामीण आवास, स्वयं सहायता समूह, पर्यटन, पर्यावरण और एग्रो टूरिज्म पर विशेष कार्य किया और जिले को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में शुमार करवाया। उसके बाद उन्हें प्रदेश का डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया गया जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल को ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में काफी सुधारा। इसके बाद उन्हें बांकुरा का कलेक्टर बनाया गया, यहां उन्होंने अपने शानदार गवर्नेंस से जिले के चहुंमुखी विकास पर खासा काम किया। लोकसभा चुनाव के दौरान मुक्ता आर्या को बांकुरा की जिम्मेदारी दी गयी थी और उन्हें चुनाव को सफल और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की वजह से काफी तारीफ मिली। मई 2019 में मुक्ता आर्या को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बतौर जिलाधिकारी नियुक्ति दी गयी। उन्होंने जिले में रूरल हाउसिंग, एसएचजी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, वूमेन इम्पॉवरमेंट और इम्पलॉयमेंट आदि पर कई महत्वपूर्ण सुधार किये। वे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'उत्कर्ष बंगाल' व 'आनंद आधार' के साथ ही नारी सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कन्याश्री, रुपाश्री और स्वप्न भोर जैसे कार्यक्रमों को हावड़ा जिले में सुदृढ़ और सुचारू तरीके से लागू करवा रही हैं। कोविड 19 के संक्रमण काल में वे जिले में साफ-सफाई, स्वच्छता, जागरूकता और गाइड लाइंस के पालन के द्वारा हालात पर काबू करने के लिए सख्ती बरत रही हैं, जिससे उनके काम की तारीफ हो रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर हावड़ा की जिलाधिकारी मुक्ता आर्या 'शक्ति' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

विकासशील

जरूरतमंदों की सेवा ही है प्रशासनिक सेवा का मकसद

सी. रविशंकर

हरिद्वार के डीएम सी. रविशंकर देश के उन चुनिंदा आईएएस अधिकारियों में से हैं जिन्हें विकास और जरूरतमंदों की मदद दोनों का पर्याय माना जाता है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा व सेवा करने की भावनाओं की चर्चा प्रदेश के लोगों से लेकर प्रशासन और सरकार के शीर्ष तक में होती रहती है। दरअसल सी. रविशंकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेवा भावना से ओत-प्रोत रही है। उनके पिता पी. चेल्ला पांडियन सरकारी नौकरी में थे और एक ग्राम सेवक के तौर पर अपनी शुरुआत कर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पहुँचे थे।

सी. रविशंकर की शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल अमरावती नगर में हुई जहां उन्होंने अनुसाशित जीवन जीने का पाठ पढ़ा। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई किया। वर्ष 2009 में आईएएस में चयन के बाद उन्हें उत्तराखंड कैडर मिला। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत एसडीएम रानीखेत से की। इसके बाद मुख्य विकास पदाधिकारी अल्मोड़ा और चमोली रहे। वे अतिरिक्त सचिव- वित्त, योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन पीएसयू के पद पर भी रहे हैं। इतना ही नहीं सी. रविशंकर ने उत्तराखंड में विदेश और विश्व बैंक की मदद से चल रही कई परियोजनाएं में परियोजना प्रबंधक के कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया।

सी रविशंकर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिलों में.डीएम रह चुके हैं। 2013 में केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण परियोजनाओं को बड़ी कुशलता अंजाम तक पहुंचाया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के लिये लाइसेंस दिलाने में अपनी कार्यशैली की मिसाल पेश की। यह एयरपोर्ट चीन-नेपाल सीमा से बेहद करीब है और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। हरिद्वार के डीएम के तौर पर सी. रविशंकर को एक संवेदनशील अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये दिन-रात जुड़े रहते हैं। बतौर हरिद्वार डीएम कोरोना संकट पर उन्होंने अपने सफल प्रशासनिक अनुभव से जीत दिलाई और जिले को कई बार कोरोना मुक्त करने में सफलता पायी है। वर्तमान में सी. रविशंकर के लिए हरिद्वार कुंभ मेला 2021 का सफल आयोजन भी एक मिशन के तौर पर भी है। सी. रविशंकर भारत-जापान द्विपक्षीय समझौतों में जापान की यात्रा पर गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाले हाई लेवल डेलीगेशन में सी. रविशंकर एक क्षेत्र स्तर के अधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी. रविशंकर 'विकासशील' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

उड़ान
★★★★★

हौसलों की ऊँची उड़ान भरने वाली सुपरवूमन
अदिति सिंह

FAME INDIA

हमेशा से ऊंची और सकारात्मक सोच, चुनौतियों से मुकाबला करने की प्रकृति और लक्ष्य के प्रति दृढ निश्चयी अदिति सिंह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सुपरवूमन के नाम से भी मशहूर हैं। यह नाम उन्हें उनकी सख्त छवि और प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण दिया गया है। करीब दो वर्षों में ही उन्होंने हापुड़ जिले की कायापलट कर दी है और हर क्षेत्र में विकास का नया ताना-बाना बुन दिया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती की रहने वाली अदिति सिंह के माता-पिता दोनों ही यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं और वे उन्हें अपना रोल मॉडल मनती हैं।

बचपन की पढ़ाई कई जिलों में हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में ग्रैजुएशन और एमए करने के बाद एम फिल भी किया। अपने माँ पापा से प्रेरणा पा कर आईएएस बनाने का निर्णय किया। 2009 में सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल की और अच्छी रैंकिंग की वजह से होम स्टेट यूपी कैडर मिला। अदिति सिंह की पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। अप्रैल 2012 में उन्हें लखनऊ का चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी बनाया गया। बतौर डीएम उनकी पहली पोस्टिंग पीलीभीत के जिलाधिकारी के तौर पर हुई। 2014 में उन्हें रायबरेली का डीएम बनाया गया। जुलाई 2014 में अदिति सिंह सुल्तानपुर की डीएम बनायी गयीं। करीब एक साल तक सुल्तानपुर में उन्होंने प्रशासनिक कौशल से जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 2015 में उन्हें यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एडिशनल मैनेजिंग डॉयरेक्टर बनाया गया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काफी सुधार किये और वहीं वो सुपरवूमन के नाम से मशहूर हुईं। इसके बाद अदिति सिंह बतौर जिलाधिकारी उन्नाव नियुक्त की गयीं। वहां भी उनकी कार्यशैली का दबदबा कायम रहा। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया, पॉल्यूशन फैलाने वाली करीब दो दर्जन औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की। उन्नाव डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड के प्रदूषण को नियंत्रित करने तक बिजली सप्लाई रुकवा कर उन्होंने अपनी मजबूत और निडर प्रशासनिक छवि का परिचय दिया और काफी चर्चा में रहीं।

अप्रैल 2018 में अदिति सिंह को हापुड़ का जिलाधिकारी बना दिया गया। उनके नेतृत्व में हापुड़ में विकास कार्यों में तेजी आयी। यह जिला 2018 से ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन सर्विस, जन शिकायत निवारण और डेवलपमेंट एजेण्डे में उत्तर प्रदेश में लगतार टॉप पर है। उन्होंने हापुड़ में स्वच्छता पर जोर दिया और भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले ग्रामीण भारत स्वच्छता मिशन सर्वे में हापुड़ देशभर में उच्च रैंकिंग हासिल करने में सफल रहा। वर्ष 2019-20 में हापुड़ जल संसाधन और सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व इकट्ठा करने वाला जिला बन गया। कोरोना काल में जागरुकता, अफवाहों पर रोक लगाने के प्रयास के साथ ही जिले में संक्रमण रोकने के हर संभव प्रयास कर अदिति सिंह शानदार गवर्नेंस का परिचय दे रही हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर हापुड़ की जिलाधिकारी अदिति सिंह 'उड़ान' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

क्षमतावान

निर्भीक और ईमानदार छवि की जिलाधिकारी
सुषमा चौहान

FAME INDIA

शुरू से ही अनुशासन पसंद रहीं सुषमा चौहान अपने मिशन के प्रति सजग रहने वाली ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी हैं। जम्मू की डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने जिले में विकास की ऐसी बयार बहा दी है कि ये इलाका प्रदेश के लिये एक मिसाल बन कर उभरा है। सुषमा ने विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से बीई की डिग्री हासिल की है। बचपन से ही आईएएस बनने की इच्छा रखने वाली सुषमा चौहान का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

पिता फौजी ऑफिसर थे इसलिये देश के विभिन्न भागों में तैनाती हुई और उनकी पढ़ाई भी कई स्कूलों में हुई। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने पहले अटेंप्ट में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की तो जम्मू-कश्मीर कैडर मिला। सुषमा चौहान ट्रेनिंग के बाद कई अहम पदों पर रहीं, इस दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को देखते कई प्रोजेक्ट पर काम किया। 2016 में जम्मू-कश्मीर की टूरिज्म डायरेक्टर पद पर रहते हुए उन्होंने जम्मू में हरियाली और पहाड़ी के बीच एडवेंचर टूरिज्म पर काफी जोर दिया। साथ पटनी टॉप से आगे एक योगा सेंटर बनाने के लिए कार्य किया। जम्मू के सुरिनसार ट्विन लेक के विकास लिए भी उनके कार्यों की काफी सराहना हुई। उन्हें जुलाई 2018 में सांबा जिले का डिप्टी कमिशनर बनाया गया। यहां उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ाया।

वर्ष 2019 में आईएएस सुषमा चौहान जम्मू कश्मीर की डिप्टी कमिशनर बनायी गयीं। वो जम्मू की कमान संभालने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं। सुषमा चौहान के क्षमतावान प्रशासनिक अनुभव और निर्भीक कार्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाये जाने से ठीक पहले यहां की जिम्मेदारी दी गयी। धारा 370 हटने के बाद उन्होंने जम्मू में शांतिपूर्ण तरीके से हालात को संभाला और लोगों में विश्वास का वातावरण बनाने में सफलता पायी। बतौर डिप्टी कमिशनर सुषमा चौहान ने जिले में प्रशासनिक सुधार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किये। इस बीच में देश में कोविड-19 आ धमका और ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गयीं। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया क्योंकि पर्यटक स्थल होने की वजह से यहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी था। उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही आपदा प्रबंधन ऐक्ट 2015 को जम्मू में लागू कर दिया। जिले में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सुषमा चौहान ने लॉक डाउन में 2.5 लाख प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था की जिससे उनके उत्कृष्ट कार्य की जमकर तारीफ हो रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर जम्मू की जिलाधिकारी सुषमा चौहान 'क्षमतावान' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

असरदार
★★★★★

असरदार तरीके से प्रशासनिक दायित्वों को निभा रहे तरुण राठी

FAME INDIA

भावुकता के साथ कर्तव्य के प्रति समर्पित तरुण राठी जिस असरदार तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं उसे देख कर उनके वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। 4 मार्च 1985 को बुलंदशहर के डिबाई में जन्मे तरुण राठी ने आरंभिक पढ़ाई कस्बे में ही की। उन्होंने श्री वार्ष्णेय कॉलेज, अलीगढ़ से स्नातक करने के बाद इग्नू से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया।

शुरुआत से ही प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले तरुण राठी का यूपीएससी 2009 बैच में आईआरएस के लिए चयन हुआ। वर्ष 2010 बैच में उन्होंने सिविल सर्विस में शानदार कामयाबी हासिल की और उन्हें 19वीं रैंक मिली और बतौर आईएएस, मध्य प्रदेश कैडर मिला। तरुण राठी को जून 2010 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। करीब एक साल से कुछ ज्यादा वक्त तक राजगढ़ में रहने के बाद उनका ट्रांसफर होशंगाबाद जिला के पिपरिया में एसडीएम बनाकर किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व क्षेत्र के वन ग्रामों के विस्थापन में उत्कृष्ट कार्य किया। इसी दौरान वे केदारनाथ त्रासदी के समय मध्यप्रदेश की राहत टीम के सदस्य के रूप में उत्तराखंड भी गये। जुलाई 2013 में तरुण राठी को नक्सल प्रभावित ज़िला बालाघाट में जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत में विकास के कई योजनाओं को मुस्तैदी के साथ लागू करवाया। मई 2015 में उन्हें खनिज संसाधन विभाग में नियुक्ति दी गयी, उन्होंने उस दौरान उल्लेखनीय कार्य किया, जिससे उनकी प्रशासनिक कार्यक्षमता की खासी तारीफ हुई।

जून 2017 में तरुण राठी शिवपुरी जिले के कलेक्टर बनाये गये जहां उन्होंने ग्रामीण आवास निर्माण में काफी बढ़िया कार्य किया। जून 2019 में तरुण राठी दमोह के कलेक्टर बने। बतौर कलेक्टर उन्होंने जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ लोगों के लिए मूलभूत सुविधा को सुनिश्चित किया। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले तरुण राठी ने दमोह में अपने काम से हर किसी का दिल जीतने की कोशिश की है। पिछले वर्ष तरुण राठी एक वृद्धाश्रम पहुंचे उन्होंने बुजुर्गों का हाल जाना। इस दौरान एक बुजुर्ग ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा जतायी, तो वे खुद अपने साथ बुजुर्ग को लेकर उनके घर पहुंच परिवारवालों से मिलाया और बच्चों को समझाकर बुजुर्ग को उनके घर पर छोड़ा। इस समाचार का अच्छा असर लोगों पर पड़ा। कोरोना काल में भी दमोह जिले में तरुण राठी ने असरदार तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस को लागू करवाया। प्रवासी मजदूरों का विशेष ध्यान रखा गया और उनके भोजन, पेयजल व आवागमन की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर दमोह के जिलाधिकारी तरुण राठी 'असरदार' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

शानदार

शानदार गवर्नेंस से सिद्ध की अपनी कार्यशैली

डॉ. मन्नान अख्तर

चिकित्सक की सरकारी नौकरी छोड़कर यूपीएससी पास कर आईएएस बनने वाले एक अधिकारी ने समस्याओं को चुनौती के तौर पर लिया और ऐसा समाधान करने का प्रयास किया कि लोगों का हरदिल अजीज बन गया। इस ऑफिसर का नाम है मन्नान अख्तर जो इस समय जालौन के जिलाधिकारी हैं। इनके पिता अख्तर हुसैन खान असम कैडर के सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं। 2011 बैच के प्रशासनिक अधिकारी मन्नान अख्तर की पत्नी सहरिश सिद्दीकी लखनऊ में तैनात आईआरपीएस अधिकारी है।

मन्नान अख्तर का जन्म असम में 27 फरवरी 1986 को हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय तेजपुर में हुई। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया। लेकिन वे सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहते थे। लिहाजा मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहे मन्नान अख्तर ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में क्वालिफाई किया। 2011 बैच के आईएएस डॉक्टर मन्नान को यूपी कैडर मिला। उन्हें मऊ जिला में प्रोबेशन पर पोस्टिंग मिली। उन्होंने गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। गोरखपुर के गांवों में सबसे ज्यादा शौचालय बनाए गए ताकि गावोंवालों को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके, इसमें काफी सफलता भी मिली। सितंबर 2017 में उन्हें जालौन का जिलाधिकारी बना कर भेजा गया। उनकी अगुवाई में जालौन में शिक्षा, जल संचयन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नियमित रूप से काम किया गया।

उन्होंने जिले में पानी की समस्या को देखते हुए जल संरक्षण पर शानदार काम किया, जिसकी बदौलत दशकों से सूखाग्रस्त रहे जालौन को जल संरक्षण के लिए नैशनल अवॉर्ड मिला। वे भूजल कोष संचय योजना के तहत लगातार कार्य करवा कर जिले के वाटर लेवल को पिछले कई बरसो पुराने स्तर पर लाने में कामयाब रहे, जिसके लिए जालौन को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। छोटे शहरों में स्वच्छता सुधार को बढ़ावा देने के मकसद से किये जाने वाले सर्वे में भी जिले का ओराई शहर नेशनल स्वच्छता सर्वे में बेहतर रैंकिंग पाने में सफल रहा। डॉ. मन्नान अख्तर ने आरबीएसके स्कीम के तहत चल रहे जालौन संवर्धन ऐप्प का बेहतर उपयोग किया, जिसकी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे हर जिलों में लागू करने के आदेश दिया। कानपुर झांसी नैशनल हाइवे 27 और साउथ-वेस्ट राज्यों को पूर्व से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के वर्षो पुराने विवाद को सुलझाने में सफल रहना इस युवा अधिकारी के शानदार व्यक्तिव और प्रशासनिक कार्य कौशल का ही कमाल रहा। कोविड-19 के संकट में भी जालौन में उनके नेतृत्व में जागरूकता, सुरक्षा, जांच, ईलाज आदि का बेहतर कार्य हो रहा है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर जालौन के जिलाधिकारी डॉ. मन्नान अख्तर 'शानदार' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

मजबूत

मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर की छवि वाले वरिंदर कुमार शर्मा

जमीन से जुड़े और अपनी भाषा से खासा लगाव रखने वाले आईएएस, हंसमुख स्वभाव के वरिंदर कुमार शर्मा आत्मविश्वास से भरे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। वे पंजाब की मिट्टी में ही पले-बढ़े हैं इसलिये वहां की रग-रग से वाकिफ हैं। वरिंदर कुमार का जन्म पंजाब में मोहाली के भागसी गांव में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता जीत राम शर्मा सरकारी स्कूल में टीचर और मां राम मूर्ति शर्मा प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थीं।

इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल और 10 वीं पटियाला जिले में लाछुर गाँव के गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इनकी पत्नी परवीन शर्मा पंजाब में इतिहास की लेक्चरार है। जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा भावना से प्रेरित वरिंदर कुमार शर्मा ने इंजीनियरिंग करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया। मातृभाषा से बेहद लगाव की वजह से उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पंजाबी में देने का फैसला किया। वे 2009 बैच में चौथे स्थान पर रहे और उन्हें पंजाब कैडर मिला।

वरिंदर कुमार शर्मा की ट्रेनिंग मुक्तसर जिले में हुई। वे जैतो और मनसा के एसडीएम भी रहे है। बाद में उन्होंने बठिंडा में विकास प्राधिकरण और नगर विकास विभाग में अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। वे फरवरी 2016 में पंजाब के मानसा जिले के डिप्टी कमीशनर बनाये गये। इस दौरान उन्होंने लैंड रिफॉर्म और सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने की दिशा में मजबूती से कार्य किया। मानसा जिले में उन्होंने कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले को नियंत्रित करने के लिए बहुत मेहनत की जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में खासी वृद्धि हुई। मार्च 2017 में वे जालंधर के जिला उपायुक्त बनाये गये। उन्होंने जालंधर में शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साफ-सफाई आदि को बेहतर बनाने को अपनी प्राथमिकता बनायी और इसमें काफी हद तक सफल रहे। वरिंदर शर्मा ने पीएपी फ्लाईओवर को दोबारा शुरू करवा कर और आदमपुर सिविल एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खुलवा कर जिले के विकास की गति को और तीव्रता प्रदान की। उनके नेतृत्व में जालंधर को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2019 में आये बाढ के दौरान उन्होंने बाढ प्रभावित क्षेत्र में लोगो की सहायता के लिए दिन रात काम किया। कोरोना संकट में उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए जागरूकता के साथ बेहतर प्रबंधन की मिसाल कायम की। वे तीन साल से जालधंर का डिप्टी कमिश्नर थे, जून 2020 में वरिंदर कुमार शर्मा को लुधियाना के जिला उपायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर जालंधर के जिलाधिकारी वरिंदर कुमार शर्मा 'मजबूत' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

जिम्मेदार

जिम्मेदारी निभा कर पहचान कायम की

शैलेश नवल

किसी भी जिले के जिलाधिकारी के पास असीमित अधिकार होते हैं और इन अधिकारों के साथ ही होते हैं कर्तव्य भी। कुछ अधिकारी इन कर्तव्यों को भी बेहद जिम्मेदारी से निभाते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। कर्तव्य पथ पर अग्रसर ऐसे ही ऑफिसर हैं अमरावती महाराष्ट्र के जिलाधिकारी शैलेश नवल जिन्हें सुधारवादी कलेक्टर के तौर पर जाना जाता है।

राजस्थान में अजमेर के बिजनेसमैन सुभाष नवल और रामा देवी के पुत्र हैं शैलेश नवल। इनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेंट आन्सेल्म स्कूल से हुई और दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने स्नातक किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री हासिल की। शैलेश नवल 2010 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस हैं। पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर सतारा में हुई। दो साल बाद वे दहानू में असिस्टेंट कलेक्टर बनाये गये। 2014 में उन्हें अहमदनगर जिला परिषद का चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। उन्होंने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किया। जिसकी वजह से उन्हें "यशवंत राव चौहान एकेडमी डेवल्पमेंट अवार्ड 2014" से सम्मानित किया गया। अहमदनगर में पंचायती परिषद को मजूबती देने के लिए उन्हें 2015 में "दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड" से भी सम्मानित किया गया।

शैलेश नवल के प्रशासनिक अनुभव बढ़ने के साथ अप्रैल 2016 में उन्हें वर्धा का कलेक्टर बनाया गया। इस दौरान शैलेश ने वर्धा जिले में नागरिक सेवा को ऑनलाइन करने पर जोर दिया। क्लेक्टरेट को पेपरलेस करने के साथ ही नागरिकों को सभी योजनाओं की जानकारी देने के मकसद से शैलेश नवल ने 'आपल्या योजना' मोबाइल एप तैयार करवाया, जिससे जिले के वार्षिक योजनाओं पर किये खर्च में पारदर्शिता आयी। वर्धा में बतौर जिलाधिकारी उन्होंने कॉटन टू क्लॉथ के माध्यम से चार गांवों में कपड़ा निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने माइक्रो एटीएम, आपने आधार आपली बैंक प्रकल्प द्वारा सैकड़ों गांवों में बैंक पहुंचाने और गांव की महिला को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। जलयुक्ति शिविर अभियान, ई-गवर्नेंस और किसानों के वेलफेयर पर काम करने के लिए 2017-18 में शैलेश नवल को 'बेस्ट कलेक्टर' चुना गया, साथ ही वर्धा को जल संचय के लिए 'बेस्ट डिस्ट्रिक्ट' का अवार्ड भी मिला। बेहतरीन कार्य कौशल को देखते हुए शैलेश नवल को फरवरी 2019 में अमरावती जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। जिले में मनरेगा को सही तरीके से लागू करवाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। कोविड 19 के कठीन काल में बेहाल महाराष्ट्र में शैलेश नवल ने अमरावती जिला में अपने उत्कृष्ट कार्यक्षमता से सबको प्रभावित किया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवल 'जिम्मेदार' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कामयाब

त्वरित फैसलों और दूरदर्शिता के दम पर कामयाब

कुमार अमित

समय के पाबंद और सजग जिलाधिकारी, देश की नामी गिरामी कंपनी में सीनियर रिसर्च इंजीनियर और बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट की लाखों की सैलरी छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आये कुमार अमित की छवि कामयाब अफसर की है। 2010 बैच के कुमार अमित वर्तमान में पटियाला के जिलाधिकारी हैं और अपने कार्यों की वजह से बेहद लोकप्रिय हैं। राजस्थान के मूल निवासी कुमार अमित ने दिल्ली के डीपीपीएस से बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद वे लार्सेन एंड टूब्रो में सीनियर रिसर्च इंजीनियर बने और मुम्बई ऑफिस में ज्वाइन किया। करीब छह महीने बाद कुमार अमित गुड़गांव में बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट के पद पर आ गये, और वहाँ वे दो साल रहे। वर्ष 2009 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वर्ष 2010 में उन्हें कामयाबी मिली और बतौर आईएएस पंजाब कैडर मिला। कुमार अमित की पहली तैनाती बठिंडा में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर हुई। उसके बाद उन्हें पंजाब के मलोट में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया। कुमार अमित की प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उन्हें जुलाई 2014 में जालंधर का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। जहाँ वे शहर के ब्यूटिफिकेशन के साथ ही लोगों की शिकायतों के निपटारे पर विशेष ध्यान दे कर वहाँ के लोकप्रिय ऑफिसर बने।

जनवरी 2016 में कुमार अमित का ट्रांसफर सीएम ऑफिस, चंडीगढ़ में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हुआ। इस दौरान उन्होंने अच्छी कार्यशैली का प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन पर विश्वास करते हुए मार्च 2017 में अपने गृह जिले पटियाला की कमान सौंपी। वे पटियाला के डिप्टी कमिश्नर बनाये गये। इस अहम जिम्मेदारी को संभालते ही उन्होंने जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाने के साथ ही पटियाला में साफ-सफाई पर बेहतरीन कार्य किया, जिसकी वजह से इन तीन वर्षों के दौरान पटियाला की नेशनल रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ। कुमार अमित के शानदार गवर्नेंस के कारण पटियाला जिला खुले में शौच से मुक्त हो गया। प्राइमरी एजुकेशन में उन्होंने "फर्स्ट सोल लैब" जैसी पहल पटियाला में की, जिसके परिणामस्वरूप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाने लगे। उन्होंने पटियाला में "अवसर प्रोजेक्ट" जैसी योजना शुरू की, जिससे हजारों बच्चों को काम के साथ शिक्षा का लाभ मिल रहा है। कुमार अमित ने वूमेन इंपावरमेंट और वूमेन हेल्थ के लिए पाकीजा प्रोजेक्ट की शुरुआत करवायी। लोकसभा चुनाव को अपनी देखरेख में निष्पक्ष तरीके से करवाया। पटियाला में कोविड 19 के इस संकट में उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन जागरुकता, इलाज आदि के साथ ही गरीबों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पटियाला के जिलाधिकारी कुमार अमित 'कामयाब' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

अनुभवी

जन-जन तक विकास पहुंचाना है प्राथमिकता

सांग फुन्सोक

FAME INDIA

अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा लेकर खुद को तराशते हुए शिखर पर चढ़ने वाले सांग फुन्सोक उच्च मनोबल के बेहतरीन इंसान हैं। अरुणाचल प्रदेश के पिछड़े जिले तवांग को उन्होंने न सिर्फ एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना डाला है, बल्कि वहां सुख-सुविधाओं की झड़ी लगा दी है। सांग फुन्सोक का जन्म अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बोमडिला गांव के सरकारी स्कूल पूरी की।

वर्ष 1987 में सांग ने केरल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुवनंतपुरम से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वे यहीं नही रूके, उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे एक असली ऑलराउंडर हैं। वे राजीव गांधी विश्वविद्यालय से एलएलबी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। सांग फुन्सोक ने इंजिनियर के तौर पर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में उत्कृष्ट सेवा देकर अरुणाचल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनायी । इंजीनियरिंग सर्विस में उनकी ईमानदारी और समर्पण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2002 में सिल्वर और वर्ष 2006 में गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया। सांग फुन्सोक को जुलाई 2016 में तवांग जिला का उपायुक्त -सह-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रुप में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में सेना सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने तवांग में स्वच्छता अभियान और पेयजल की सुविधा को प्राथमिकता दी, जिसके कारण ड्रिंकिंग वॉटर एडं सैनिटेशन मिनिस्ट्री ने वर्ष 2018 में तवांग की व्यवस्था को पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बेहतर मान कर सम्मानित किया।

सांग फुन्सोक ने राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के महत्वपूर्ण अभियान "सरकार आपके द्वार" से तवांग के सुदूर गांवों तक को जोड़ कर हर जरूरी सेवा मुहैया कराने में सफलता प्राप्त की। राज्य सरकार ने "सरकार आपके द्वार" की सफलता के लिए वर्ष 2019 में उन्हें गोल्ड मेडल दिया। उन्होंने आम लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ा और जिले में शांति व एकता के प्रतीक 'मैत्री दिवस' और 'तवांग - फेस्टिवल' का सफलता पूर्वक आयोजन कराया। अरुणाचल में ठंड के मौसम में बिजली की समस्या एक गंभीर मसला रहती थी, सांग फुन्सोक ने अपने अनुभव से इसमें सुधार कर तवांग में 24X7 इलेक्ट्रिक सप्लाई सुनिश्चित करवायी। सांग फुन्सोक ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में सफलता पूर्वक निष्पक्ष चुनाव करवाया, जिससे उनके प्रशासनिक अनुभव की सराहना हुई है। सांग फुन्सोक ने कोरोना संकट में जिले में जागरुकता को तरजीह देते हुए इस महामारी पर काबू पाने में सफलता पाई। प्रशासनिक तत्परता की वजह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाना उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर तवांग के जिलाधिकारी सांग फुन्सोक 'अनुभवी' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

शोहरतमंद

जन-भागीदारी और जवाबदेही को तरजीह देते डॉ. नरेंद्र कुमार मीणा

एक शख्स की जिसने बचपन से आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा और अपना लक्ष्य पा ही लिया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीणा 2010 बैच के आईएएस और वर्तमान में देवभूमि द्वारका के जिलाधिकारी हैं। राजस्थान के दौसा जिला के झाझीरामपुरा में 31 अगस्त 1983 को जन्मे नरेंद्र कुमार मीणा पढ़ने लिखने में अच्छे स्टूडेंट थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के नरेंद्र की बचपन से साहित्य में गहरी रूचि थी। उन्होंने जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी किया।

डॉ. नरेंद्र कुमार मीणा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 2007 से अगस्त 2010 तक बीएचयू में छात्र को पढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आईएएस बनने में सफल हुए। ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद इनकी पहली नियुक्ति गुजरात के वलसाड में हुई फिर हलोल में असिस्टेंट कलेक्टर बने। फरवरी 2014 में मेहसाणा के डिस्ट्रिक्ट डेवल्पमेंट ऑफिसर बने। लोहा और स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध मेहसाणा में उन्होंने पर्यावरण के लिये काफी काम किया। वहाँ के बाद उन्हें राज्य के वडोदरा जिले में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया। यहां उन्होंने स्वच्छता मिशन के प्रति लोगों को जागरूक किया। वर्ष 2016 में वड़ोडरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये उन्होंने दिन-रात एक करके काम किया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने वडोदरा के लोगों से स्मार्ट सिटी से जोड़ने के लिए फीड बैक लिया। जिसमें व्हाट्सऐप्प, ट्विटर और फेसबुक के जरिये लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट, क्राइम कंट्रोल, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट पर अहम सुझाव दिये। इस तरह प्रशासन में आम जन की भागीदारी बढ़ाकर नरेद्र कुमार मीणा ने अपनी अलग पहचान बनायी।

नरेंद्र कुमार मीणा को अगस्त 2017 में प्रदेश मुख्यालय गांधीनगर में एडिशनल डेवल्पमेंट कमिश्नर बनाया गया। यहां उन्होंने मुख्य तौर पर पंचायतों के आधुनिकीकरण पर कार्य किया और गुजरात के करीब 14,000 पंचायतों के विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। उनकी बनायी योजना पर राज्य सरकार अब कार्य भी कर रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीणा को फरवरी 2019 में देवभूमि द्वारका का जिलाधिकारी बनाया गया। जून 2019 में आये भयंकर तूफान वायु के बचाव कार्य में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कोरोना काल में समुद्र मार्ग के जरिये विदेशों से आने वालों को क्वारंटीन करवाने में सख्ती से कार्य किया। द्वारकाधीश मंदिर के ऑनलाइन दर्शनों की शुरुआत उन्होंने अप्रैल में ही करवा दी। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने देश में सबसे अधिक 450 करोड़ रुपये दिलवाये। वे जन भागीदारी और बेहतरीन कार्य के लिए जाने जाते है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर देवभूमि द्वारका के जिलाधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार मीणा 'शोहरतमंद' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कर्मठ ★★★★★

कर्मठता से कायम की पहचान
निधि श्रीवास्तव

1980 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर एक लोकप्रिय सीरियल आया "उड़ान"। ये सीरियल एक आईपीएस अधिकारी की रीयल लाइफ स्टोरी पर बना था। सफलता की एक ऐसी ही दास्तान है निधि श्रीवास्तव की, जिन्होंने न सिर्फ सिविल सर्विसेज की परीक्षा में टॉप रैंकिंग हासिल की बल्कि अपनी कार्यकुशलता के दम पर एक लोकप्रिय अधिकारी भी साबित हो रही हैं। उन्हें 2010 में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिली। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है।

जब उनका चयन सिविल सर्विस के लिये हुआ तब वे कानून में मास्टर्स डिग्री के लिये पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने कुछ दिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत भी की। 2 सितंबर 1989 को गाजियाबाद में जन्मीं निधि अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। वर्तमान में सेंट्रल दिल्ली की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य के लिए जानी जाती हैं। आईएएस में चयन के बाद उन्हें एजीयूएमटी कैडर मिला। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले पूर्वी सियांग में वे बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात रहीं। वहां उन्होंने जनजातीय और ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों की समस्या पर जोरदार तरीके से काम किया। साथ ही शहरी नवीनीकरण में पुराने संसाधनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जिससे 100 स्मार्ट सिटी में उनके जिले को स्थान मिला। 2012 से 2015 तक अरूणाचल प्रदेश में रहने के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ।

सितंबर 2015 में दिल्ली आने के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में रेवन्यू डायरेक्टर बनाया गया। उन पर दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व को सही करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बिना पैसा चुकाये पानी का इस्तेमाल करने वालों की पहचान करवायी और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। अप्रैल 2018 में डिप्टी कमिश्नर साउथ दिल्ली साथ ही उन्हें दिल्ली स्मार्ट सिटी, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीईओ भी बनाया गया। उन्होंने साउथ दिल्ली में स्वच्छता और विकास के काम को बढ़ावा देने के साथ रिन्युएबल एनर्जी पर जोर दिया। इस दरम्यान उन्होंने सफलता पूर्वक लोकसभा चुनाव भी करवाया। सितंबर 2019 में निधि श्रीवास्तव सेंट्रल दिल्ली की जिलाधिकारी बनायी गयीं। कोरोना की जंग में वे बढ़-चढ़ कर कार्य कर रही हैं। उन्होंने प्रवासियों को घर भेजने से लेकर सेंट्रल दिल्ली में रह रहे आम लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं को मुहैया कराने में पूरी ताकत झोंक डाली है। वे बिना थके अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। हालांकि इसी दौरान उन्हें केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें बतौर डीएम जारी रखा गया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर दिल्ली सेंट्रल की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव 'कर्मठ' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

विलक्षण ★★★★★

विलक्षण प्रतिभा के धनी

डॉ. त्यागराजन एस. एम .

कहते हैं चुनौतियां हमेशा हौसलों का इम्तिहान लेती हैं। इसी सोच को मापदंड बनाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के बावजूद डॉ. त्यागराजन एस. एम . ने आईएएस की परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण हुए। देश के विकास में अपनी भागीदारी के मकसद से प्रशासनिक सेवा में आये। वर्ष 2011 बैच के आईएएस डॉ. त्यागराजन एस. एम . शालीन, व्यवहार कुशल, कर्मठ और ईमानदार जिलाधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं।

20 दिसंबर 1984 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में जन्मे त्यागराजन शुरुआत से ही सिविल सर्विस में जाने की इच्छा रखते थे ।उनके पिता एस मोहन राम और माता उमा देवी का परिवार मध्यम वर्गीय था। पढाई में विलक्षण डॉ. त्यागराजन ने 2008 में कोयंबटूर के एमजीआर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, परन्तु लक्ष्य सिविल सर्विस का था। वर्ष 2010 में उन्होंने आईपीएस कंप्लीट कर बतौर एएसपी ओडिशा में ज्वाइन किया, वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये चुने गये और बिहार कैडर मिला। डॉक्टर त्यागराजन एसएम का प्रशासनिक सफर बिहार के पूर्णिया से शुरू हुआ जहां वे प्रशिक्षु थे। उनकी पहली पोस्टिंग एसडीओ पटना सिटी हुई थी। फिर बिहार शरीफ में नगर निगम के आयुक्त बनाये गये। आयुक्त रहते हुए उन्होंने सफाई के क्षेत्र में कई बेहतर कार्य किये। उनकी ईमानदारी और प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्ठा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अगस्त 2015 में अपने जिले नालंदा का डीएम बनाया। इस दौरान इनकी दृढ़ इच्छाशक्ति वजह से नालंदा शहर स्मार्ट सिटी की रेस में आ गया। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में राजगीर के भूई गांव में ठोस कचरा प्रबंधन को नया आयाम दिया। उन्होंने बेहतरीन कार्य कौशल के बल पर एकंगरसराय प्रखंड के चम्हेडा को मॉडल गांव के रूप में विकसित करवाया। नालंदा में विद्युतीकरण कार्य बेहतर तरीके से कराने के लिये प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया।

2019 फरवरी में डॉ. त्यागराजन एस. एम . दरभंगा जिला के जिलाधिकारी बनाये गये। आम तौर पर शांत और मृदुल स्वभाव के डॉ त्यागराजन निर्भिक और त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। दरभंगा आने के साथ ही उन्होंने प्रशासनिक सुधार के काम में गति और विकास कार्यों को रफ्तार दिया। कोरोना काल में डॉ. त्यागराजन एस. एम. के कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। कोविड से जिले को सुरक्षित रखने के साथ उन्होंने लॉकडाउन में जिले की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हजारों योजनाएं प्रारंभ करवाई , इन कार्यों में 50,000 से अधिक मजदूरों को काम मिला , मजदूरो को रोजगार देन के लिए बांधों की सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करवाना उनकी विलक्षण कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। चुनौतियों से विचलित न होने वाले डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम. की यही कार्यशैली उन्हें विलक्षण बनाती है ।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम . 'विलक्षण' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

दूरदर्शी

सपनों को हकीकत में बदलने वाले दूरदर्शी वैभव श्रीवास्तव

सपने देखना और उसे साकार कर लेना हर किसी के वश में नही होता, परन्तु सपने को हकीकत में परिवर्तित करने का जज्बा रखने वाले इंसान कम ही होते हैं। ऐसे ही एक दूरदर्शी अधिकारी हैं वैभव श्रीवास्तव जो जहां भी तैनात रहे, वहां विकास कार्यों से ऐसा सकारात्मक माहौल तैयार किया कि लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। बचपन से लक्ष्य के प्रति सकारात्मक वैभव शिक्षित और संभ्रांत परिवार से हैं। उनके पिता कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, बड़े भाई इंजीनियर, बड़ी बहन डायरेक्टर स्पोर्ट्स (छत्तीसगढ़) और पत्नी नेहा प्रकाश 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 1 जुलाई 1981 को जन्मे वैभव का बचपन से ही मैथ्स से लगाव रहा। बोर्ड की परीक्षा में उन्हें मैथ्स में 100 में 100 फीसदी अंक आये। लेकिन मां और बड़ी बहन की प्रेरणा से उन्होंने सिविल सर्विसेज के लक्ष्य को पाने के लिए ह्यूमनिटी से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने हिंदी से एमए में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। यूपीएससी में सफल होने से पहले वैभव मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सफल हुए। वैभव श्रीवास्तव 2009 बैच में आईएएस बने। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासनिक सेवा की बारीकियों को समझा। 1 मई 2015 को वैभव श्रीवास्तव को मऊ का जिलाधिकारी बनाया गया, जहाँ सफलता पूर्वक पंचायत चुनाव करवाने की वजह से उन्हें सर्वश्रेष्ठ डीईओ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां उन्होंने निर्मल तमस अभियान भी चलाया जो काफी सफल रहा। उन्हें स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवॉर्ड भी मिला।

वर्ष 2016 में वैभव श्रीवास्तव अंबेडकरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया। उन्होंने अंबेडकरनगर में सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात और शिक्षकों की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षादूत नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन बेस कार्यक्रम शुरू किया। वर्तमान में प्रदेश सरकार का प्रेरणा कार्यक्रम भी इसी पर आधारित हैं। बतौर डीएम उन्होंने अंबेडकरनगर में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराया और सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पुरस्कार से नवाजे गये। फरवरी 2019 में वैभव श्रीवास्तव को पीलीभीत का जिलाधिकारी बनाया गया। वहाँ उनके द्वारा शुरू किये गये पराली प्रबंधन योजना को राज्य सरकार रोल मॉडल के तौर पर सभी जिलों में लागू करने का प्रयास कर रही है। दूरदर्शी वैभव श्रीवास्तव ने जिले में जल संचयन और जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए मात्र एक साल के कार्यकाल में जिले में करीब 1800 तालाब का निर्माण, पुनरुद्धार कार्य करवाया, जिससे पीलीभीत का भूजल स्तर पिछले दस साल के पुराने स्तर पर आ गया। कोरोना संक्रमण काल में पीलीभीत जिले में इनके द्वारा किये जा रहे प्रयास और योजना को कारगर और सफल प्रशासनिक प्रयासों को डीएम के तौर पर इनकी सफलता मानी जा रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव 'दूरदर्शी' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

बुलंद

बुलंद इरादे के जिलाधिकारी हैं
डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे

वैसे तो चिकित्सा को समाजसेवा का सबसे उम्दा जरिया कहा जाता है, लेकिन आईएएस की सर्विस में समाजसेवा के साथ-साथ समाज सुधार का भी अवसर मिलता है। इन्हीं विचारों के साथ डॉक्टर नीलेश ने एमबीबीएस करने के बाद भी प्रशासनिक सेवा में अपना कैरीयर चुना। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ नीलेश देवरे महाराष्ट्र के नासिक जिले से हैं। इनके परिवार में पढ़ाई की प्राथमिकता रही है और उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे।

डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे और महाराष्ट्र बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में बैच टॉपर थे। उन्होंने मुंबई के तेरणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल से एमबीबीएस किया। डॉ. रामचंद्र देवरे शुरुआत से ही जुझारू और बुलंद व्यक्तित्व के रहे हैं। वर्ष 2011 में वे आईएएस बने और बिहार कैडर मिला, डॉ नीलेश बाढ़ सब-डिविजन में एसडीएम रहे है। इसके बाद गया नगर निगम में म्युनिसिपल कमिश्नर बने। वहां के प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में उन्होंने जो व्यवस्था करवायी उसकी जमकर सराहना हुई। उत्कृष्ट सेवा के लिये बिहार के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सम्मानित किया। नीलेश देवरे बांका और पश्चिमी चम्पारण की कमान संभाल चुके हैं। बांका में कांवरिया मेला में आधारभूत संरचना निर्माण, बौंसी मंदार पर्वत का टूरिज्म प्लान एवं मंदार पर्वत पर रोपवे के शुरुआती कार्य के साथ साथ सरकार के सात निश्चयों में बनने वाले सभी संस्थानों को जमीन उपलब्ध कराने का कार्य उनके कार्यकाल में हुआ।

31 जुलाई 2017 को वे जैसे ही पश्चिमी चंपारण के डीएम बने वैसे ही अगले कुछ दिनों में वहां बाढ़ ने अपनी भयंकर विभीषिका दिखायी। पीड़ितों के दर्द को खुद का दर्द समझकर उन्होंने राहत के लिये दिन-रात काम किया। उन्होंने बेतिया शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलवा कर वहां के लोगों के दिल में खास जगह बनायी। सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करने वाले इस युवा अधिकारी ने कलेक्ट्रिएट नाम से पेज बना कर प्रशासन की हर लोक कल्याणकारी योजना की घोषणा की और वहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन कर उनका निवारण भी किया। पश्चिमी चम्पारण में ये प्रयोग पहली बार हुआ था और काफी सफल रहा। डॉ. नीलेश देवरे का प्रशासनिक जिम्मेदारी और आम लोगों से जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। फिलहाल वे मधुबनी के जिलाधिकारी हैं, जहाँ वे कोरोना काल में सरकार की गाइड्लाइंस को सख्ती से पालन करवाने पर बल दे है। वे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिले के हर क्षेत्र की जानकारी लेने के साथ हीं जिले भर में हर संभव निरीक्षण भी कर रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर मधुबनी के जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे 'बुलंद' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

जागरूक ★★★★★

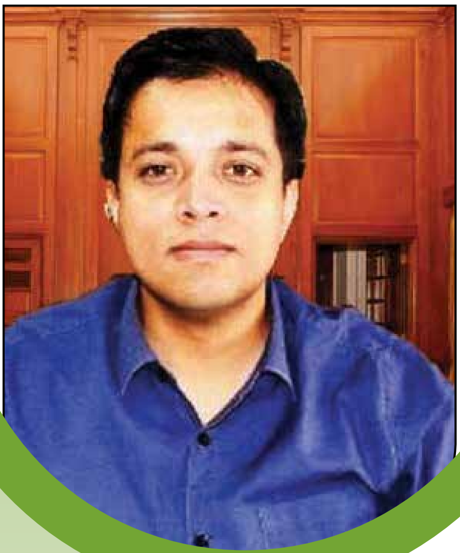

जागरूकता और जवाबदेह कार्यशैली की मिसाल हैं विवेक भाटिया

चंबा के डिप्टी कमिशनर विवेक भाटिया को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ विकास और जनकल्याण को आगे बढ़ाने के लिये जाना जाता है। वे एक दूरदर्शी, अनुभवी और जिम्मेदार अधिकारी हैं। मूल-रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी विवेक भाटिया का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। विवेक की स्कूलिंग डीपीएस डलहौजी से हुई।

वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश के एनआईटी हमीरपुर में दाखिला मिल गया जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बतौर इंजीनियर काम भी किया, लेकिन पर्वत की ऊंचाइयों के बीच पले-बढ़े इस नौजवान का लक्ष्य आईएएस बनना था। वर्ष 2011 में उनका सिविल सर्विस में चयन हुआ और हिमाचल प्रदेश कैडर मिला। जनवरी 2016 में विवेक की शादी हमीरपुर की ही शिखा शर्मा से हुई। डॉ शिखा चंबा मेडिकल कॉलेज में बतौर सिनियर रेजिडेंट कार्यरत हैं। उनकी 2011 में पहली पोस्टिंग राज्य के सिरमौर जिले के सुदूर ब्लॉक शिलाई में हुई। इसके बाद जिला किन्नौर के निचार और जिला मंडी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट रहे। फिर उन्हें धर्मशाला का लैंड सेटलमेंट ऑफिसर बनाया गया, जहां उन्होंने भूमि संबंधित रिकॉर्ड और चकबंदी संबंधी निपटारों में हुए सुधारों को सख्ती से लागू किया।

वर्ष 2016-17 में विवेक भाटिया को लाहौल और स्पीति का डिप्टी कमिशनर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक रूप से लाहौल स्पीति बेहद दुर्गम स्थान है। यहां चुनौतियां अद्वितीय हैं लेकिन इसके बावजूद युवा डीसी विवेक ने इस इलाके के आदिवासी लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। इनके कार्यकाल में कई सुदूर गाँव बड़े बड़े पुलों के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़े। इसके बाद उनका ट्रांसफर शिमला हुआ , जहां लैंड रिकॉर्ड, फूड एंड सिविल सप्लाईज और ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर पद पर रहे। वर्ष 2018 में उनका ट्रांसफर बतौर डिप्ट्री कमिशनर बिलासपुर हुआ। वहां उन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य-कुशलता से कई परियोजनाओं को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, जिनमें से एम्स, रेलवे लाइन और फोर लेन स्टेट हाइवे उल्लेखनीय हैं। विवेक भाटिया को वर्ष 2019 में चंबा जिले की कमान सौंपी गयी। अपनी बेहतरीन कार्य-क्षमता से योजनाओं पर तेजी से कार्य करते हुए महज एक वर्ष में उन्होंने इस जिले में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास व बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया।जिसमें उनके कार्यों की सराहना हो रही है। वर्तमान में कोरोना सकंट से जंग में वे बेहतर भूमिका निभा रहे है और सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल कर जागरूकता का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर चंबा के जिलाधिकारी विवेक भाटिया 'जागरूक' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

बेजोड़

सादगी और सेवा की मिसाल हैं

राहुल कुमार

भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस को भले ही देश की सबसे ग्लैमरस जॉब माना जाता है, लेकिन कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें लोग उनकी सादगी के लिये पहचानते हैं। पूर्णिया के वर्तमान जिलाधिकारी राहुल कुमार एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने लोगों के करीब जाकर उनकी समस्याओं को जाना-समझा और सुलझाया है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में 6 मार्च 1987 को एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे राहुल कुमार के पिता शिक्षक और माँ गृहणी हैं।

राहुल कुमार ने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की, वर्ष 2010 में यूपीएससी की परीक्षा में उनका चयन आईपीएस में और वर्ष 2011 में आईएएस के लिए हुआ। उन्होंने अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से लीडरशिप प्रोग्राम की पढ़ाई भी की है। ट्रेनिंग के बाद पटना जिले के दानापुर के एसडीएम के तौर उन्होंने प्रशासनिक बारीकियां सीखीं और इस दौरान ही वे अपनी निर्भीकता की वजह से चर्चा में रहे, उनका बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथरिटी की जमीन को लेकर एक एडीजी से विवाद हो गया, और उनकी रिपोर्ट पर सरकार ने कड़ी कारवाई की ।इसके बाद उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में एसएचएस का एडिशनल एक्सक्यूटिव डायरेक्टर और साथ ही बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई।

वहां से वे गोपालगंज के डीएम बनाए गये। 2015 दिसंबर में उन्होंने स्कूल में उस महिला के हाथों बना हुआ मिड डे मील खा कर स्थानीय दबंगों की बोलती बंद की,जो उसे डायन बताने की कोशिश कर रहे थे। इसकी चर्चा देश भर में मिसाल के तौर पर हुई । उन्होंने जिले को खुले में शौच से मुक्त करने में अहम भूमिका निभायी जिससे लोग उन्हें 'सैनिटेशन हीरो' कहकर पुकारने लगे। बेगुसराय के जिलाधिकारी के तौर पर उन्होंने महज 16 महीने में जिले को ओडीएफ का दर्जा दिलवा दिया। बेगुसराय में उन्होंने अनुकंपा से जुड़े मामले, स्वैच्छिक सेवानिवृति, विभागीय कार्यवाई को बेहतरीन तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। उन्हें नीति आयोग की ओर से बेगुसराय के समावेशी विकास के लिए 'चैंपियन ऑफ चेंज' अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राहुल कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वे वर्ष 2018 में बेगुसराय में 100 फीसदी विद्युतीकरण के लिये सीएम और उसी वर्ष कौशल विकास के लिए राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित किये गये। सितंबर 2019 में राहुल कुमार पूर्णिया के डीएम बनाये गये। उन्होंने वर्ष 2020 की शुरुआत में बेहद सफल रहे किताब दान अभियान चलाया। कोरोना काल में उनके कई कार्यों की चर्चा देश भर में हो रही है। दूसरे राज्यों से अपने होम डिस्ट्रिक्ट लौटे लोगों को रोजगार मुहैया कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार 'बेजोड़' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

शख्सियत

कर्म को सफलता का राज मानते हैं

यशेंद्र सिंह

यशेंद्र सिंह का पैतृक स्थान हरियाणा के जींद जिले में पड़ता हैं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। 2011 बैच के यशेंद्र सिंह को शुरुआती पोस्टिंग मिली गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। वहां उन्होंने अनुकरणीय सुधार किया और पहली बार इस नगर में ऑर्गनाइज्ड सिटी बस सर्विस शुरू की। यह सिलसिला आगे बढ़ा और प्रशासनिक सुधार को उन्होंने सार्वजनिक सेवा से जोड़कर अपनी प्रतिबद्धता दिखायी। उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे रेवाड़ी के प्रशासन को लोकप्रिय और अत्यधिक कुशल बनाया जा सका। फरवरी 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 'सक्षम' परीक्षा में रेवाड़ी को रैंक-1 हासिल हुआ। इस परीक्षा में छात्रों के सीखने के लेवल की जांच होती है। इतना ही नहीं उनके नेतृत्व में हरियाणा के सार्वजनिक सेवा वितरण मंच में 'अंत्योदय सरल' में भी रेवाड़ी पहले नंबर पर रहा।

बतौर जिलाधिकारी इन्होंने विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान आम जनता को जागरूक करने में अहम भूमिका निभायी और उन्हें 'बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। उनकी प्रशासनिक सूझबूझ की वजह से रेवाड़ी में सड़क हादसों में करीब 40 प्वाइंट की कमी आयी और सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 2016 में 870 थी, 2019 मे बढ़कर 919 हो गयी है। उन्होंने रेवाड़ी जिले में युवाओं में अनुशासन और सेहतमंद जीवन के लिये 'स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ राष्ट्र', 'रन फॉर यूथ' राष्ट्रीय युवा दिवस मैराथन का आयोजन करवाया, जिसमें करीब 50 हजार से अधिक स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यशेन्द्र सिंह की कार्यशैली की बदौलत रेवाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर 'ग्रामीण स्वच्छता अवार्ड 2019' मिला है। कर्म को पूजा मामने वाले यशेन्द्र सिंह ने कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। परिणाम यह रहा कि कोरोना वायरस से रेवाड़ी जिला प्रदेश में सबसे कम प्रभावित रहा। उन्होंने 25 हजार प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को सुनिश्चित किया और उनके खाने व चिकित्सा आदि की व्यवस्था करवायी। प्रदेश के राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उनके कार्यों की तारीफ कर चुके हैं।

हरियाणा में रेवाड़ी के जिलाधिकारी यशेन्द्र सिंह अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। प्रशासन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में उन्हें महारत हासिल है। उनकी नजर में कर्म ही सर्वाधिक प्रधान है। यशेन्द्र सिंह का जन्म रोहतक में हुआ। वे शिक्षा और प्रशासनिक बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर रेवाड़ी के जिलाधिकारी यशेंद्र सिंह 'शख्सियत' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

जज्बा

जज्बात के साथ फर्ज निभाने के लिए जाने जाते हैं

राय महिमापत रे

झारखंड की राजधानी रांची की प्रशासनिक व्यवस्था एक तरफ जहां राज्य सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहती है वहीं दूसरी तरफ यहां मौजूद तमाम महकमों और मुख्यालयों को सुविधाएं प्रदान करना भी जिला प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वहां के जिला उपायुक्त की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे वर्तमान में सुनियोजित तरीके से संभाल रहे हैं 2011 बैच के आईएएस राय महिमापत रे।

राय महिमापत रे के पिता राय उमापत रे यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, वे प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके थे और उनकी मां विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं। राय महिमापत रे का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ और शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के ला मार्टिनियर में हुई। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक और 2005 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर्स करने के बाद वहीं से एम फिल भी किया। शुरुआती दिनों में राय महिमापत ने एक शिक्षक के रूप में देश के युवाओं को नई राह देने का निर्णय लिया, लिहाजा उन्होंने दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दो साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि प्रशासनिक सेवा में जा कर समाज में तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। 2011 में उन्हें सफलता मिली और झारखंड कैडर मिला।

पहली पोस्टिंग खूंटी के सब डिविजन मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। एक साल बाद राय महिमापत रे को हजारीबाग के जिला पंचायत का चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर फिर लातेहार का डिप्टी कमिश्नर और इसके बाद बोकारो का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। बोकरो में उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किया, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी का प्रोमोशन, पूर्वी भारत में बोकारो को सबसे साफ-सुथरा शहर बनाना, सबसे ज्यादा टॉयलेट बनवाना, डिजि-धन मेला का आयोजन और एन एच 23 और 32 को फोर लेन बनाने जैसे काम प्रमुख रहे। डिजिटल इकोनॉमी के प्रोमोशन के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया, वहीं बोकारो को साफ-सुथरा शहर बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अवॉर्ड मिला। राय महिमापत रे को सोशल डिसएबिलिट मिनिस्ट्री की ओर से प्रशस्ति-पत्र भी मिला। सबसे अहम बात ये है कि बोकारो डीसी के रूप में महिमापत रे के कार्यों की नीति आयोग ने भी तारीफ की। खासकर, कुपोषण रोकने के लिए 'पोषण ऐप्प' शुरू करने पर नीति आयोग ने प्रजेंटेशन के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया। फरवरी 2018 में राय महिमापत रे को रांची का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। जिले में जल शक्ति अभियान युद्ध स्तर पर शुरू करवा कर राय महिमापत रे ने प्रशासनिक कौशल को स्थापित किया। इसकी सराहना खुद पीएम मोदी ने की है। इनके नेतृत्व में कोविड 19 के काल में संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट के मामले में रांची मॉडल बना। महिमापत रे कोरोना की जंग में समाजिक सहयोग से टीम वर्क नीति पर काम कर रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर रांची के जिलाधिकारी राय महिमापत रे 'जज्बा' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

प्रेरक ★★★★★

प्रेरक व्यक्तित्व और लोकप्रियता की मिसाल हैं

मंगेश घिल्डियाल

FAME INDIA

ऊँची सोच के मेहनती इंसान हैं मंगेश घिल्डियाल। वे फिलहाल टिहरी के जिलाधिकारी हैं और अपनी दूरदर्शिता, योजनाबद्धता और निर्णयों को कार्यरूप देने की क्षमता के कारण उन्हें विकास पुरुष का दर्जा हासिल है। पौड़ी गढ़वाल जिले के टांडियों गांव में 06 अगस्त 1986 को प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बृजमोहन घिल्डियाल और आरती देवी के घर मंगेश का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि थे।

उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन और एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ फिजिक्स, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से लेजर साइंस में एमटेक भी किया। वर्ष 2008 में बतौर रक्षा साइंटिस्ट मंगेश घिल्डियाल की पहली पोस्टिंग डीआरडीओ, देहरादून में हुई। परन्तु अपनों के लिए कुछ करने की चाहत में वे साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ सिविल सर्विस में जाने की तैयारी में जुट गये। उन्होंने पहली बार में ही 131वीं रैंक हासिल की और उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ। लेकिन उनकी चाहत और मंजिल आईएएस बन कर पहाड़ की सेवा करने की थी। दोबारा यूपीएससी 2012 बैच की सिविल सर्विसेज परीक्षा में वे चौथे स्थान पर रहे, और उन्होंने उत्तराखंड कैडर चुना।

मंगेश घिल्डियाल की पहली पोस्टिंग लक्सर हरिद्वार में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। इसके बाद चमोली में मुख्य विकास अधिकारी रहते हुए उन्होंने चमोली जिले को खुले में शौच से मुक्त करवाया। उनके नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चमोली जिले को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2016 में मंगेश घिल्डियाल बागेश्वर के जिलाधिकारी बनाये गये। मात्र सात माह के कार्यकाल में ही अपनी विशेष कार्यशैली से उन्होंने जनता का दिल जीत लिया। यही कारण था कि जब उनका स्थानांतरण हुआ तो जनता सड़कों पर उतर आयी थी। 17 मई 2017 को मंगेश घिल्डियाल रुद्रप्रयाग के 23वें जिलाधिकारी बने। जिले में विकास कार्यों को उन्होंने तेजी से शुरू करवाया। विकास के प्रति उनके गहरे लगाव का अहसास तब भी देखने को मिला जब रुद्रप्रयाग के जीजीआईसी में उन्हें साइंस सहित कई टीचर्स के पद खाली होने का पता चला तो अपनी पत्नी डॉ ऊषा सुयाल घिल्डियाल को नौवीं और दसवीं की छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाने भेज दिया। रुद्रप्रयाग में मंगेश घिल्डियाल के रहते हुए ज़िले को देश में प्रधान मंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें दो बार मुख्यमंत्री सुशासन एवं उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019-20 के लिए ज़िले को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार में प्रथम स्थान (गोल्ड मैडल) प्राप्त हुआ। ज़िले के तीन प्रोजेक्ट्स को स्कॉच आर्डर और मेरिट अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ है। रुद्रप्रयाग में तीन साल रहने के बाद मई 2020 में उनका ट्रांसफर टिहरी हो गया। कोविड-19 महामारी के इस संकट में ज्वाइन करते ही मंगेश घिल्डियाल ने टिहरी जिले में बेहतर व्यवस्था के साथ डॉक्टरों की सूची तैयार करवायी ताकि कोरोना इंफेक्शन के दौरान इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना आये।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल 'प्रेरक' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

लगनशील

★★★★★

देश के लिए कुछ करने की भावना से आईएएस बने

रजत बंसल

आईएएस बनने वाले लगनशील अधिकारीयों में एक हैं रजत बंसल, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर ठान लें तो समाज कों बदला जा सकता है। ये उनकी लगन का नतीजा है कि वे जहां भी रहे विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा निवासी रजत के परिवार में पढ़ाई की प्रधानता रही है। उनके पिता इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे।

शुरुआती पढ़ाई ला मार्टीनियर स्कूल लखनऊ में हुई। स्कूलिंग दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम से हुई। उन्होंने 2009 में बिट्स-पिलानी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वे 2009 से अप्रैल 2011 तक इंफोसिस पुणे में जूनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पर कार्यरत रहे। इंफोसिस में नौकरी के दौरान ही उन्होंने आईएएस बनने के लिये सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हिस्सा लिया। पहले प्रयास में उनका चयन आईपीएस में हुआ लेकिन दूसरे प्रयास में आईएएस के लिये चुन लिये गये। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल को छतीसगढ़ कैडर मिला। रजत बंसल की पहली पोस्टिंग रायगढ़ में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई। अगस्त 2014 से 2015 तक वे राजनंदगांव के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाये गये। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद उन्होंने दिन-रात एक कर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा और विकास पर जोर दिया। इसके बाद वे सूरजपुर जिले में जिला पंचायत के सीईओ बनाये गये।

ब्यूरोक्रेसी के सफर के अगले पड़ाव में वे जून 2016 से फरवरी 2019 तक प्रदेश की राजधानी रायपुर में नगर निगम आयुक्त के पद पर रहे। रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में पूरी लगन से कार्य किया। उन्होंने 'मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी' का स्लोगन दिया। रजत बंसल के कार्यों की उपलब्धियों में रायपुर में 'कचरा महोत्सव' का आयोजन भी रहा है। पीएम मोदी ने स्वच्छता के लिए डीएम के आइडिया को इनोवेटिव बताते हुए 'मन की बात' में शेयर और तारीफ भी की। फरवरी 2019 में धमतरी के जिलाधिकारी बने ,पद भार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले को डेंगू मुक्त करने की ठान ली । जिसमें वे काफी हद तक सफल रहे। प्रशासनिक स्तर पर काम सुचारू और समय से हो इसके लिए धमतरी में पहली बार बायोमीट्रिक सिस्टम हर दफ्तर में लगाया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान ही रजत बंसल बस्तर के डीएम बनाये गये हैं। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को सफलतापूर्वक संभालने के लिये उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता से काफी प्रशंसा मिली। वे आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। रजत बंसल का मानना है कि पद के बजाए आदमी को आदमी की तरह समझने और भावनाओं का कद्र करके समस्या का समाधान तेजी से किया जा सकता है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर बस्तर के जिलाधिकारी रजत बंसल 'लगनशील' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

प्रशंसनीय
★★★★★

अहम फैसले लेने की प्रशंसनीय क्षमता वाले अनंत लाल ज्ञानी

स्वभाव से हंसमुख, लेकिन कार्य के लिए प्रतिबद्ध और विकास में योगदान सुनिश्चित करने वाले अनंत लाल ज्ञानी अहम फैसले लेने में ज्यादा समय नही लगाते। डेवलपमेंट के कार्यों में किसी भी तरह की देरी को अन्याय मानने वाले अनंत लाल ज्ञानी वर्तमान में असम के धुबरी जिले के कलेक्टर हैं।

अनंत लाल ज्ञानी का जन्म 1 मार्च 1981 को बिहार के नवादा जिले में हुआ। उन्होंने नवादा के गांधी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद मगध विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक किया और इसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने 2011 बैच में कामयाबी हासिल की और उन्हें असम-मेघालय कैडर मिला। प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर उन्होंने कई अहम दायित्वों का निर्वहन किया। उनके उत्कृष्ट कार्य-कौशल को देखते हुए उन्हें असम के नलबाड़ी जिले का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। यहाँ उन्होंने शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसके बाद अनंत लाल ज्ञानी को धुबरी जिले की कमान दी गयी, जहाँ उन्होंने जिले के विकास के लिए एक से एक प्रयोग शुरू किये। "अभ्योदय" उनमें से एक है। यह एक क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है। अभ्योदय काफी पॉपुलर शिक्षण कार्यक्रम साबित हुआ। नीति आयोग ने धुबरी जिले को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस के लिये रिवार्ड दिया। राज्य सरकार ने शिक्षा के इस प्रोग्राम को रोल मॉडल के तौर पर लिया। उन्होंने जिले में शिक्षा के अलावा पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

धुबरी में स्वच्छता मिशन के तहत घर घर से कचरे को उठाने के अभियान की शुरुआत हो या स्टोन क्रशर मशीन को बंद करके प्रदूषण रोकने और माफियाओं पर लगाम लगाने का प्रयास, अनंत लाल ज्ञानी हर मोर्चे पर निडरता से निर्णय लेने को लेकर मशहूर है। लोकसभा चुनाव में भी उनके काम की तारीफ हुई। उन्होंने अंधेरे में डूबे गांवों में उजाला फैलाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सोलर पॉवर ग्रिड लगवाया जो वाकई चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनके कार्यशैली से धुबरी जिले के ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी नीति आयोग ने विशेष तौर पर सराहा है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से इस जिले के 85 प्रतिशत लोगों को कवर करवाया, जिससे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विशेष प्रशंसा मिली। पोषण अभियान में भी धुबरी ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दो पुरस्कार प्राप्त किये। वे नलबाड़ी और धुबरी दोनों ही जिलों को शत प्रतिशत खुले में शौच से मुक्ति दिलाने में कामयाबी रहे और पुरस्कृत भी हुए। धुबरी में कोरोना नियंत्रण के लिए उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन सख्ती से कार्य कर रहा है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर धुबरी के जिलाधिकारी अनंत लाल ज्ञानी 'प्रशंसनीय' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कलात्मक

प्रशासनिक कलात्मकता के कारण देश भर में विख्यात

के. राजेश

मोटिवेशनल स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर, सिंगर, राइटर, बैडमिंटन प्लेयर और कई अन्य कलात्मक खूबियां गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के उपायुक्त कनकीपति राजेश को औरों से थोड़ा अलग बनाती हैं ईमानदारी को अपना सबसे मजबूत पक्ष मानने वाले के. राजेश ने सामाजिक समरसता और विकास को ध्येय मानकर प्रशासनिक सेवा में आने का फैसला किया। यही नतीजा है कि वे एक अधिकारी के तौर पर विकासवाद का पर्याय बने हुए हैं।

23 मार्च 1986 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जन्मे के.राजेश ने पाँडीचेरी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वे यूनेस्को स्कॉलरशिप ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स से सम्मानित हैं। के.राजेश 2011 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। के राजेश पहली पोस्टिंग में जूनागढ़ के असिस्टेंट कलेक्टर बनाये गये। सितबंर 2013 में उनका ट्रांसफर सूरत के बारडोली में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर किया गया। 2015 में उन्हें मोरबी का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया। गुजरात के इस औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने विकास को नया आयाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे सूरत में भी डीडीओ रहे। इस दौरान गुजरात सरकार द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ डीडीओ के सम्मान से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2018 में के. राजेश को सुरेंद्रनगर का जिलाधिकारी बनाया गया। इस जिले में उन्होंने कृषि, कृषक और गरीब व आम लोगों के लिए जबरदस्त कार्य किया।

सुरेन्द्रनगर जिला कलेक्टर और एक आईएएस अधिकारी के तौर पर उनकी एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने डफर समुदाय (देश के अन्य राज्यों में इन्हे बंजारा, खानाबदोश आदि कहते हैं) के हजारों परिवारों को जीने की नयी दिशा दी। बरसों से हर सुविधा से वंचित रहे इस समुदाय के लोगों को उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि के साथ ही आवासीय जमीन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1000 से ज्यादा घर उपलब्ध करवाया। ये देश भर में किसी प्रशासनिक अधिकारी के प्रयास की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने जिले में सिंचाई परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही जिले के सभी किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने पर बल दिया। उनका प्रयास है कि किसान मजबूत और सुरक्षित महसूस करेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी और इससे देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत और उनकी आमदनी दोगुनी सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किया जिसकी काफी सराहना हो रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर लोकसभा चुनाव में के राजेश द्वारा चलाये गये मतदाता जागरूकता अभियान की भी सराहना हुई। कोविड-19 कोरोना काल में गुजरात के बेदम होने की स्थिति में भी उन्होंने सुरेंद्र नगर में प्रशासनिक दायित्वों को जवाबदेही से निभाया है। वे आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी तेजी से काम कर रहे हैं ताकि कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी को कम किया जा सके।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर सुरेंद्र नगर के जिलाधिकारी के. राजेश 'कलात्मक' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

व्यवहार कुशल

व्यवहार कुशलता में सर्वोच्च हैं

नवनीत सिंह चहल

एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्होंने विदेश की बेहतरीन नौकरी छोड़ कर अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की चाहत में अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की उन्होंने कायापलट कर देश के साफ-सुथरे जिलों में शामिल करवा दिया। 14 मई 1984 को पानीपत, हरियाणा के एक सुशिक्षित व संपन्न परिवार में नवनीत का जन्म हुआ। पिता सत्यपाल सिंह चहल नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, पानीपत इकाई में अधिकारी और माता परवीन चहल गर्वनमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानीपत में इतिहास की लेक्चरर थी।

उन्होंने 12वीं में टॉप किया और पीईसी चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर एमडीआई, गुरुग्राम से फाइनेंस और मार्केटिग में एमबीए करने के बाद पेरिस से फाइनेंस मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। फाइनेंसियल एनालिस्ट के पद पर तीन साल तक न्यूयॉर्क/मुम्बई में कार्यरत रहे, परन्तु दिल में देश के लिए कुछ करने की इच्छा लगातार बनी रही। उन्होंने वापस लौटने का मन बना लिया और वर्ष 2011 में यूपीएससी की परिक्षा पास की। बतौर आईएएस उन्हें यूपी कैडर मिला। नवनीत सिंह चहल की पहली पोस्टिंग बहराइच जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। वहाँ से मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और फिर मेरठ में ही चीफ डेवल्पमेंट ऑफिसर बनाये गये। नवनीत सिंह चहल झांसी में भी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर रहे।

2017 में वे अमरोहा के जिलाधिकारी बनाये गये। अमरोहा में उन्होंने खाद्यान वितरण में धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। खुले में शौच के विरूद्ध जनजागरण के लिए 'तिगरी मेला' के आयोजन के दौरान 30 हजार से अधिक स्टूडेंट्स का ह्यूमन चेन बनवा रिकॉर्ड कायम किया। मार्च 2018 में नवनीत सिंह चहल को चंदौली जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। जिले की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने 'ब्लैक राइस' के जरिये जिले को नयी पहचान दिलायी। उन्होंने चंदौली में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 'शिक्षित एवं सुपोषित चंदौली' योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जिले में वालंटियर टीचर के कांसेप्ट को आगे बढ़ाया, जो काफी सफल साबित हुआ। उन्होंने सामाजिक सहभागिता से लोगों को कुपोषित बच्चों को गोद लेने को प्रेरित किया जिसका बहुत ही शानदार परिणाम सामने आया। व्यवहार कुशल नवनीत सिंह चहल के नेतृत्व में चंदौली ने हेल्थ, पोषण, रोजगार और मनरेगा के क्षेत्र में अहम प्रगति की जिससे इस जिले ने नीति आयोग द्वारा जिलों की होने वाली रैंकिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन रैंकिंग के कारण केंद्र सरकार से जिले के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का इनाम भी मिला। चंदौली को लंबे समय तक कोरोना मुक्त जिला बनाये रखने के लिए नवनीत सिंह चहल की जमकर तारीफ हो रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर चंदौली के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल 'व्यवहार कुशल' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

दक्ष

दक्षता से प्रशासनिक कार्यो को निभाने वाले राग़ुल के.

FAME INDIA

जिओ इंफॉर्मेटिक्स विषय मे बीटेक की डिग्री, आईआईएम से मैनेजमेंट में डिप्लोमा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक और फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में लाखों रुपये का पैकेज। इसके बावजूद राग़ुल के. को आकर्षित कर रहा था एक ऐसा करीयर जिसमें संभावना थी दुर्गम इलाकों में समाज की समस्याओं से जूझने की जिम्मेदारी मिलने की। सबकुछ जानते हुए भी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई और आज वे एक लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं। बेहद सुलझे और विनम्र राग़ुल के. वर्तमान में साउथ सिक्किम के जिला उपायुक्त हैं।

तमिलनाडु के शिक्षित मध्यमवर्गीय परिवार में एल. कस्तुरीरंगन और के.कोकिला के घर 18 सितंबर 1986 को राग़ुल के. का जन्म रानीपेट जिले के वाजापेट में हुआ। उन्होंने रानीपेट के वेदवल्ली विद्यालय से और रामकृष्ण सीनियर सेकेंड्री स्कूल से बारहवीं किया। राग़ुल के. ने अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जिओ इंफॉर्मेटिक्स से बीटेक करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैंगलोर से एमबीए भी किया। वर्ष 2008-09 में वे रिजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नागपुर में वैज्ञानिक थे। इसके बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ज्वाइन किया, लेकिन उनका मन इन सब से हटकर कुछ अलग करने का था, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का मन बनाया और वर्ष 2012 में यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। उन्हें सिक्किम कैडर मिला।

राग़ुल के.को साउथ सिक्किम के नामची में बतौर प्रशिक्षु असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। वे करीब एक साल तक नामची के एसडीएम भी रहे। इसके बाद वे गैंगटोक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाये गये। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, और साथ ही किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले इसलिए मिडलमैन के प्रचलन पर रोक लगाते हुए ऐसी व्यवस्था को बढावा दिया जिसमें किसानों को सीधे अपने प्रोडक्ट्स बेचने का अवसर प्राप्त हो। राहुल के. दो वर्षों के लिए सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाये गये। इस दौरान उन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के तमाम प्रयासों के साथ ही दुग्ध उत्पादकों की स्थिति को बेहतर बनाने पर भी अच्छा कार्य किया। फरवरी 2019 में राग़ुल के को साउथ सिक्किम का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। वे पहले भी यहां बतौर एडीएम, एसडीएम कार्य कर चुके थे। जिले में विकास की संभावनाओं से परिचित राग़ुल के. ने मक्का की खेती, रोजगार के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ की बेहतर प्रशासनिक कार्यों की वजह से जल्दी ही उनकी छवि साउथ सिक्किम के लोगों के बीच एक लोकप्रिय जिलाधिकारी की बन गयी। कोरोना संकट के दौर में बतौर जिलाधिकारी राग़ुल के. साउथ सिक्किम में कोरोना के संक्रमण को रोकने में सक्षम माने जा रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर दक्षिण सिक्किम के जिलाधिकारी राग़ुल के. 'दक्ष' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

उद्देश्यपूर्ण

सामाजिक कुरीतियों को दूर करना ही उद्देश्य

डॉ. ऋचा वर्मा

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से अपनी प्रशासनिक क्षमता सिद्ध कर चुकी डॉ ऋचा वर्मा ने समाज में विकास कार्य के उद्देश्य से आईएएस बनने का निर्णय लिया। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने पीजीआईएमएस रोहतक से बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री ली है। उनके पिता नरेंद्र कुमार वर्मा सरकारी सेवा में रहे और मां किरण देवी गृहिणी हैं। ऋचा वर्मा का जन्म 10 सितंबर 1986 को हरियाणा के यमुनानगर में हुआ।

उनकी शुरुआती पढ़ाई अबांला के पीकेआर जैन पब्लिक स्कूल और बारहवीं चमनलाल डीएवी पब्लिक स्कूल,पंचकुला से हुई। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय किया और यूपीएससी की परीक्षा में 2012 बैच में उन्हें आईएएस बनने में कामयाबी मिली। इनके पति नीरज कुमार आईएफएस अधिकारी हैं। डॉ. ऋचा की पहली पोस्टिंग सोलन के असिस्टेंट कमीशनर के पद पर हुई। वे डलहौजी और नहन की एसडीएम रही हैं, जहाँ उन्होंने राजस्व और भूमि संबंधी कई सुधार किये। अप्रैल 2018 में डॉ ऋचा वर्मा को हमीरपुर जिले का डिप्टी कमीशनर बनाया गया। उन्होंने हमीरपुर जिले में महिला कल्याण के लिए बेहतरीन काम किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2018 में उनके नेतृत्व में हमीरपुर को पोषण के क्षेत्र में पहले स्थान पर पाया और सर्वश्रेष्ठ जिले के अवार्ड से सम्मानित किया। नीति आयोग ने डॉ. रिचा वर्मा को हमीरपुर में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए छठवें जेआरडी टाटा मेमोरियल अवॉर्ड से सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने हमीरपुर में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर उत्कृष्ट काम किया, स्कूलों में बच्चियों की निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग करवाई, परिणामतः लड़कियों की शिक्षा में भी हमीरपुर देश का अव्वल जिला बना।

नशीले पदार्थ के सेवन और तस्करी को भी खत्म करने के लिए उन्होंने सकारात्मक कोशिश की, जिसमें डॉ ऋचा काफी कामयाबी भी रही। डॉक्टर ऋचा वर्मा की पोस्टिंग कुल्लू जिले में बतौर डिप्टी कमिशनर की गयी। जून 2019 में पद भार संभालने के साथ ही उन्होंने कुल्लू जिले में कचरा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यटन, बाल विकास जैसे क्षेत्रों में कार्यों को बखूबी बढ़ावा दिया। उन्होंने कुल्लू-मनाली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी और प्रभावी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित किया। 'संवेदना' नाम से महिलाओं के हाइजीन के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। डॉ. ऋचा ने समाजिक सहभागिता से "बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आंगनबाड़ी गोद लेने का कार्यक्रम" को सफलता से आगे बढाया। इस प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट में कुल्लू जिले को शॉर्टलिस्ट किया गया। कोरोना संकट में कुल्लू जिले में हो रहे कार्य के लिए भी उनकी तारीफ हो रही है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर कुल्लू की जिलाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा 'उद्देश्यपूर्ण' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

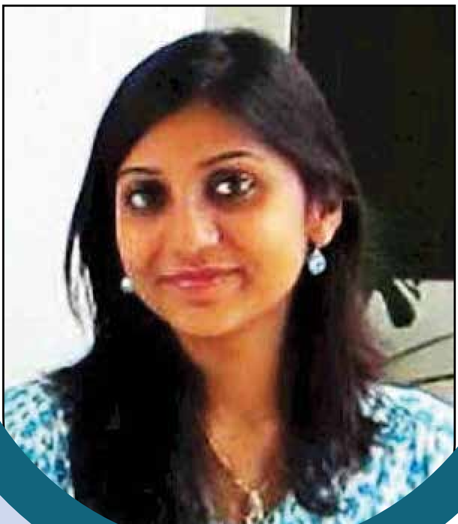

उम्दा ★★★★★

सादगी ने बनाया उम्दा जिलाधिकारी

स्वाति एस. भदौरिया

स्वाति एस. भदौरिया नाम है एक ऐसी शख्सियत का जिन्हें कर्तव्यनिष्ठा और सादगी की वजह से उम्दा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। वे जरूरतमंदों के विकास को देश की तरक्की से जोड़कर देखती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली स्वाति श्रीवास्तव का परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा है। उनकी स्कूली शिक्षा गोरखपुर के लिटिल फ्लॉवर स्कूल से हुई।

लखनऊ के आईईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बीटेक (ऑनर्स) करने के बाद उनका चयन भारतीय रिजर्व बैंक के लिये हो गया, जहां उन्होंने छह महीने काम भी किया। 2012 में आईएएस में चुने जाने के बाद स्वाति को छतीसगढ़ कैडर मिला। स्वाति की शादी नितिन भदौरिया से हुई जो 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड में पोस्टेड हैं। विवाह के बाद स्वाति 2015 में उत्तराखंड कैडर में पोस्टेड हुई, जहाँ उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मसूरी और देहरादून के रूप में उनका बेहद सफल कार्यकाल रहा। दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग कास्ट से होने के बावजूद ये एक अरेंज्ड मैरिज रहा क्योंकि रिश्ते से पहले वे दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। उत्तराखंड में वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विभागों में अतिरिक्त सचिव के साथ एडिशनल सीईओ, उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पदों पर रही और अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से एक अलग पहचान बनायी। स्वाति हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी रहीं हैं। जुलाई 2018 में वे चमौली जिले की जिलाधिकारी बनीं। बतौर जिलाधिकारी वे अपने प्रशासनिक कार्यों को बखूबी निभा रही हैं। चमौली में डीएम रहते हुए उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन आंगनबाड़ी सेंटर में कराकर एक मिसाल पेश की।

स्वाति एस. भदौरिया को उम्दा बनाने के पीछे उनकी सोच है, जिसके तहत उन्होंने आमलोगों के लिए कई अहम प्रोजेक्ट शुरू किया। ये खास प्रोजेक्ट्स हैं-बचपन (बच्चों की प्रगति और पोषण के लिए बेहतर आंगनबाड़ी)। उन्होंने पंच बद्री प्रसादम परियोजना की भी शुरुआत करवायी जिसके तहत वहां के लोग तुलसी, स्थानीय जड़ी-बूटियों की धूप, अखरोट, चौलाई के लड्डु, सरस्वती और कैलाश मानसरोवर का जल एक सरकारी व्यवस्था के तहत तैयार करते हैं। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका मिल रही है। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत करवायी है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग क्लास भी उनकी पहल का ही नतीजा है। स्थानीय उपज को बढ़ावा देने के लिए संडे बाजार और बागवानी आउटलेट का विकास करना उनकी विकासवादी सोच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। जिले में एंडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने और नये पर्यटन स्थलों का विकास करना उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया 'उम्दा' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

भविष्यवादी

भविष्य की संभावनाओं के योजनाकार जिलाधिकारी
डॉ. पीयूष सिंगला

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के हिमायती, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विकास की योजना बनाने में माहिर डॉ पीयूष सिंगला जम्मू कश्मीर कैडर के 2012 बैच के आईएएस हैं। वे वर्तमान में उधमपुर जिले के कलेक्टर हैं। उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे प्रशासक की बनायी है जो न सिर्फ फ्युचरिस्टिक प्लानिंग करते हैं बल्कि उनपर तत्परता से अमल भी करते हैं। पीयूष सिंगला का जन्म 1 नवंबर 1986 को पंजाब के पटियाला में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई मोहाली के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हुई।

इंटरमीडियेट के बाद कुशाग्र बुद्धि पीयूष का चयन मेडिकल में हो गया और उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। 2010 में इंटर्नशिप के दौरान सामाजिक विकास को दिशा देने के मकसद से प्रशासनिक सेवा में आने का मन बनाया। वे बतौर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल में भी पोस्टेड रहे। 2012 में प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिये गये और उन्हें जम्मू कश्मीर कैडर मिला। पहली पोस्टिंग में डॉ पीयूष सिंगला जम्मू में रेवन्यू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बनाये गये। करीब एक साल के बाद उन्हें जम्मू का एसडीएम बनाया गया। फरवरी 2016 में उन्हें माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एडिशनल सीईओ बनाया गया। श्राईन बोर्ड में नियुक्ति के दौरान उन्होंने वहां के तत्कालीन सीईओ ए के साहू के साथ मिलकर माता वैष्णो देवी की यात्रा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सराहनीय योगदान दिया। डॉ. पीयूष सिंगला को बतौर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जिले की कमान सौंपी गयी। इस दौरान डॉक्टर सिंगला ने कठिन परिस्थितियों में श्री अमरनाथजी यात्रा का सफल संचालन करते हुए गांदरबल को तरक्की की नई ऊँचाईयों पर ले कर गए। उन्हें 'वर्ल्ड टॉलेट डे' पर भारत के टॉप 10 कलेक्टरों में शुमार किया गया। इसके बाद उन्हें कठुआ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गयी जहां उन्होंने ग्रामीण लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और शांति व्यवस्था को कायम रखने को प्राथमिकता दी।

जुलाई 2019 में डॉ. पीयूष सिंगला को उधमपुर का डिप्टी कमिशनर बनाया गया। जिले में स्वच्छता मिशन, गांवों को सड़को से जोड़ने के कार्य, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जीविका प्रोजेक्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल पर बेहतर प्रदर्शन किया। डॉ पीयूष सिंगला को वर्ष 2020 में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर का अवार्ड दिया गया और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए उधमपुर को साल 2020 में 'सकून प्रोजेक्ट' के लिए नैशनल ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल हासिल हुआ। कोरोना काल में भी डॉ. पीयूष सिंगला के कार्यों की जमकर तारीफ हो रही है। 'राशन ऑन व्हील' उनका एक ऐसा प्रयोग था जिसकी चर्चा देश भर में हुई। कोरोना काल में बोर्ड में पास होने वाले बच्चों के लिए 'बैक टू स्कूल' के तहत एडमिशन की शुरुआत करवायी।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर उधमपुर के जिलाधिकारी डॉ पीयूष सिंगला 'भविष्यवादी' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

ऊर्जावान

सेवा को पहली प्राथमिकता मानते हैं
पी. बी. नूह

एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी समझदारी और ठोस कदमों से हर मुश्किल को जीतने का आसान नुस्खा बना लिया। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हर मुश्किल घड़ी को मिटा देने का हुनर जानने वाले इस ऑफिसर ने कम समय में ही वो लोकप्रियता हासिल की है जो कई फिल्मी सितारों और नेताओं को भी नहीं मिल पाती। केरल के छोटे से जिले पथानमथिट्टा के जिलाधिकारी पीबी नूह बावा को सुपरहीरो का दर्जा हासिल है।

पी. बी. नूह का जन्म केरल के पेरुम्बावूर में हुआ। पी. बी. नूह की स्कूलिंग एर्नाकुलम से हुई। उन्होंने जूलॉजी पढ़ने के बाद एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर से बीएससी एग्रीकल्चर और इसी विषय में पोस्ट ग्रैजुएशन की। शुरुआत में सभी बच्चों की तरह वे डॉक्टर बनना चाहते थे और बाद में कृषि वैज्ञानिक, लेकिन, बड़े भाई पी बी. सलीम के आईएएस बनने के बाद उन्होंने भी प्रशासनिक सेवा में ही जाने का फैसला लिया। पहले प्रयास में आईएफएस मिला लेकिन 2012 में दूसरी बार सिविल सर्विसेज में देश भर में 48वीं पोजीशन मिली और बतौर आईएएस केरल कैडर मिला। ट्रेनिंग के बाद पी. बी. नूह बावा की पहली पोस्टिंग ओट्टाप्पलम में बतौर सब डिविजिनल ऑफिसर हुई। इसके बाद उन्हें ट्राइबल वेल्फेयर और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाया गया। सितंबर 2017 में उन्हें सोशल जस्टिस एंड इंपॉवरमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया। पी. बी. नूह को जून 2018 में पथानमथिट्टा जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। उस दौरान उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ा था। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की हिदायत दी थी, लेकिन तभी भयंकर बाढ़ ने जन-जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बतौर जिलाधिकारी उन्होंने फौरन प्रशासन की कमान संभाली। सोशल मीडिया पर उन्होंने स्थानीय वॉलंटियर्स से मदद मांगी। हजारों की संख्या में लोगों को जमा किया और बाढ़ राहत व स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया।

फरवरी महीने में कोरोना ने देश में पहली बार केरल में दस्तक दे दी तो पथानमथिट्टा में ही सबसे पहला मामला आया। इटली से वापस लौटे एक परिवार ने अपनी जानकारी छुपा कर लोगों के बीच इंफेक्शन फैला दिया। ऐसे में पीबी नूह ने मरीजों की पहचान करने के लिये वैज्ञानिक तरीके से फ्लोचार्ट का विधि को अपनाया। कम से कम 1300 सौ लोगों की पहचान की गयी और सभी को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन सेंटर से कोई शख्स ना भागे इसके लिए खास जिओफेंसिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया। अब ये एप्लीकेशन सभी जगह कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दूर-दराज के इलाकों में वे कई किलोमीटर खुद चल कर राशन पहुंचाने गये। पथानमथिट्टा के विधायक के सा थ पीठ पर राशन के बोरे को लादकर नदी पार करने वाली उनकी तस्वीर सोशल व मेनस्ट्रीम मीडिया पर खूब लोकप्रिय हुई।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर पथानमथिट्टा के जिलाधिकारी पी. बी. नूह भावा 'ऊर्जावान' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

कुशल प्रबंधन

कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान है

ओम प्रकाश कसेरा

विनम्रता और सादगी के साथ ही कुशल प्रशासक भी हैं कोटा के वर्तमान जिलाधिकारी ओम प्रकाश कसेरा। राजस्थान के कोटा शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिये उन्हें काफी प्रशंसा मिली है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों, वहां देश भर से पढ़ने आये स्टूडेंट्स और व्यापारियों आदि की परेशानियों के निपटारे के लिये एक सुदृढ़ व्यवस्था बनायी है। राजस्थान के श्रीमाधोपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी एस एल कसेरा के घर 5 अक्टूबर 1982 को ओम प्रकाश कसेरा का जन्म हुआ। सदैव स्कूल की परीक्षाओं में टॉपर रहने वाले ओम प्रकाश ने 2003 में बीकॉम में कॉलेज टॉप किया।

ओम प्रकाश कसेरा 2005 में एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उसके बाद उन्होंने सीए और सीएस की पढ़ाई की। 2009 में सीए करने के बाद वर्ल्ड बैंक में रिसर्च एनालिस्ट के पद पर रहे। फ़रवरी 2010 से अगस्त 2012 तक ओएनजीसी में फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर रहे, लेकिन उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा था। वर्ष 2012 में वे यूपीएससी की परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ सफल रहे, और उन्हें राजस्थान कैडर मिला। ओम प्रकाश कसेरा को अजमेर का असिस्टेंट कलेक्टर और एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया। इसके बाद उन्हें राजस्थान के बारां में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया। वर्ष 2015 में उन्हें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। जुलाई 2017 में ओम प्रकाश कसेरा जोधपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमीशनर बनाये गये।

बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर उन्होंने जोधपुर नगरनिगम में व्याप्त अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाये। जुलाई 2018 में उन्हें जैसलमेर का जिलाधिकारी बनाया गया। इसके बाद 2019 में उन्हें राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन का डायरेक्टर बनाया गया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय सुधार किए। जिससे उनके कार्य की जमकर तारीफ हुई। सितंबर 2019 में ओम प्रकाश कसेरा कोटा के जिलाधिकारी बनाये गये। कोटा देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, लिहाजा उन्होंने कोटा में छात्रों की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई सुधार के साथ वहाँ के अन्य प्रबंधनो को भी दुरूस्त किया। कोरोना महामारी के दौर में बतौर जिलाधिकारी ओम प्रकाश कसेरा की चुनौतियां काफी बड़ी थी, जिले की आम जनता के साथ ही हजारों की संख्या में कोटा में रहने वाले दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जिले की जनता को जागरूक करने के साथ ही उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को नकारात्मक विचार से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली। मुश्किल हालात में स्टूडेंट्स के लिए बेहतर प्रबंधन क्षमता की वजह से उनके काम की देश भर में सराहना हुई।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर कोटा के जिलाधिकारी ओम प्रकाश कसेरा 'कुशल प्रबंधन' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

चर्चित

शानदार गवर्नेंस व दूरदर्शी निर्णयों के चर्चित कलेक्टर

प्रिंस धवन

FAME INDIA

ईटानगर हो या लोहित, आईआईटी से एम टेक टेक्नोक्रैट ने जिले के विकास के लिए कई ऐसे निर्णय किये, जिससे इस युवा अधिकारी की चर्चा सब ओर हो रही है। प्रिंस धवन ऐसे जिलाधिकारी हैं जो जहां भी रहे विकास की नयी ईबारत लिखते रहे। मात्र 23 साल की उम्र में यूपीएससी की परिक्षा में तीसरे रैंक हासिल करने वाले प्रिंस 2012 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस हैं। चंडीगढ़ के प्रिंस धवन के पिता इंडियन रेवन्यू सर्विस में थे। उन्होंने इंदौर से 12वीं करने के बाद आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक भी किया।

प्रशासनिक सेवा का विचार उनके मन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आया। माता-पिता को अपना आदर्श मानने वाले प्रिंस ने सिविल सर्विस के लिए जबरदस्त मेहनत की और पहली ही कोशिश में उन्होंने 2012 बैच में यूपीएससी में कामयाबी हासिल की, जिसमें उनका रैंक तीसरा रहा। ट्रेनिंग के बाद प्रिंस धवन चंडीगढ़ में एसडीएम और लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर के तौर पर सुर्खियों में रहे। इसके बाद उन्हें अरूणाचल प्रदेश में आईटी डिपार्टमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया। उनके नेतृत्व में विभाग को बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट का अवॉर्ड मिला। उनकी क्षमताओं को देख कर उन्हें प्रदेश की राजधानी ईटानगर के डीसी की जिम्मेदारी दी गयी। उन्होंने अपना प्रशासनिक कौशल को दिखाते हुए ईटानगर को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की। उन्होंने जिले में स्वच्छता मिशन, पब्लिक सैनिटेशन, सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया।

पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार किसी डीसी ऑफिस को पेपरलेस बनाने के लिये उन्हें नैशनल ई गवर्नेंस अवॉर्ड मिला। जिले के लोगों की आर्थिक मजबूती के लिए उन्होंने बांस की खेती को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभायी। ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होने की वजह से वहाँ की लॉ एंड आर्डर को व्यवस्थित करने के लिए बतौर डिप्टी कमिश्नर प्रिंस धवन ने कई अहम निर्णय लिये। उन्हें अरुणाचल सरकार से उत्कृष्ट डिप्टी कमिश्नर चुन कर गोल्ड मैडल भी प्रदान किया गया। मार्च 2019 में प्रिंस धवन को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। वहाँ भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के सुधार को प्राथमिकता दी और जिले में पारदर्शी कार्य संस्कृति और सर्विलांस बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने जिले में ऑर्गेनिक चाय की खेती की संभावना को देखते हुए उसे बढ़ावा दिया। लोहित को वे हर तरह से अरूणाचल के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 कोरोना संकट के इस समय वे जिले को संक्रमण से बचाने का सतर्कता के साथ प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोहित जिले मे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम जन को मंदी के दौर में भी आर्थिक संबल मिल सके।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर लोहित के जिलाधिकारी प्रिंस धवन 'चर्चित' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

संवाद क्षमता

संवाद क्षमता के धनी

अजय कटेसरिया

अजय कटेसरिया की पहली पोस्टिंग 2013 में होशंगाबाद में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर हुई। इसके बाद उन्हें मुरैना के सबलगढ़ का सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया जहां एसडीएम रहते हुए इनके त्वरित निर्णय लेने और आम जनता से संवाद की बेहतर क्षमता प्रशासनिक महकमे में चर्चा का विषय रहा। सबलगढ़ में भी अतिक्रमण हटाने के मामले में भी उन्होंने काफी सख्त रुख अपनाया। वर्ष 2015 में अजय कटेसरिया को टीकमगढ़ जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया। इसके बाद उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी राजस्व और राहत एवं पुनर्वास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बी.पी. सिंह विशेष अभियान के तहत राजस्व विभाग की कमान संभाले हुए थे। इसके उपरान्त युवा ऑफिसर अजय को अशोकनगर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया। अशोक नगर में प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने से उनकी नयी पहचान बनी।

फरवरी 2020 में अजय कटेसरिया का ट्रान्सफर सतना के डीएम के तौर पर हुआ। जिला सतना में आते ही इन्होने बरसों से विलम्ब हो रहे बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि नेशनल हाईवे हेतु भूमि-अर्जन, मेडिकल कॉलेज की भूमि से अतिक्रमण हटाने, वृहद् जल-आपूति योजना हेतु भूमि आवंटन पर तेज़ी से काम किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी 46100 किसानों से रिकॉर्ड 3.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो किसी भी वर्ष से अधिक था। सहकारिता माफिया और अतिक्रमण के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान शुरू किया। बतौर जिलाधिकारी उन्होंने इतने कम समय में अपने कार्यों से सबको प्रभावित कर दिया और आम लोग में लोकप्रिय हो गये। इस बीच कोरोना संक्रमण की आहट से जिलाधिकारी अजय कटेसरिया ने तमाम प्लानिंग के साथ कोरोना के लिए विशेष व्यवस्था की। इनके नेतृत्व में लॉकडाउन में सतना जिला में करीब तीस हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था, सामूहिक रसोई और 23 हजार मजदूरों को एक हजार रुपए का राहत पैकेज दिया गया, वहीं मझगवां और परसमनिया के लगभग साढ़े छह हजार आदिवासी परिवारों को जरूरी सामानों की सप्लाई सुनिश्चित की गयी। बेहतर संवाद क्षमता का परिचय देते हुए इन्होंने मैहर शारदा देवी धाम एवं चित्रकूट धाम को पुजारियों एवं समाज को विश्वास में लेते हुए लॉक-डाउन से पहले ही बंद करवा दिया।

प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारियों और मुश्किलों के तनाव को खुद पर कभी हावी होने नहीं देने वाले सतना के जिलाधिकारी अजय कटेसरिया हंसमुख स्वभाव के हैं। इनका जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा झारखंड के धनबाद में हुई। बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेज और अनुशासित स्टूडेंट रहे अजय की शुरुआती शिक्षा कोयला नगरी में ही हुई। देश और समाज की सेवा को लक्ष्य मानकर उन्होंने सिविल सर्विस में शामिल होने का सपना देखा जो वर्ष 2012 में पूरा हुआ। आईएएस में चयन होने के बाद उन्हें मध्यप्रदेश कैडर मिला।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर सतना के जिलाधिकारी अजय कटेसरिया 'संवाद क्षमता' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

आईकॉन

चैम्पियंस ऑफ चेंज

संदीप सिंह

एक शानदार अमेरिकी कंपनी में लाखों रुपये की सैलरी वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर वापस भारत लौटना। सिविल सर्विसेज की कठिन परीक्षा दो बार क्वालिफाई करना और झारखंड के पिछड़े जंगली इलाकों को विकास की राह पर ले जाने का कठिन कार्य। ये निश्चित तौर पर कोई मिशनरी ही कर सकता है। युवा जोश से भरपूर रामगढ़ के जिलाधिकारी संदीप सिंह एक ऐसे ही यूथ आईकॉन हैं।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शिक्षक विजय पाल सिंह के पुत्र संदीप की आठवीं तक की पढ़ाई भी उसी स्कूल में हुई, जहां उनके पिता शिक्षक थे। उन्होंने रायबरेली के ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से बारहवीं और फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। वे कानपुर के एचबीटीआई से एमसीए करने के बाद तीन साल मल्टीनेशनल कंपनी मे बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत रहे। इस क्रम में वह 6 महीने अमेरिका के टेक्सास में भी कार्यरत रहे। वर्ष 2009 के अंत में सॉफ्टवेयर छोड़कर संदीप सिंह वर्ष 2010 में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए और आईपीएस के लिये चयनित हुए, जिसमें उन्हें होम कैडर यूपी मिला। 2012 में पुनः उनका सेलेक्शन आईएएस के लिए हुआ और झारखंड कैडर मिला। बतौर प्रशिक्षु संदीप सिंह झारखंड के सिमडेगा में असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट भू-राजस्व बनाये गये।

संदीप सिंह ने चतरा डीसी रहने के दौरान मनरेगा व अन्य विकास योजनाओं में ज़मीनी स्तर पर गड़बड़ी को दूर करने व अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रभावी ऐक्शन लिया। फरवरी 2018 में उन्हें साहिबगंज का उपायुक्त बनाया गया। इस जिले में उन्होंने मल्टी मॉडल बंदरगाह के कार्य में तेजी लाने व इसका निर्माण अपने कार्यकाल में पूर्ण कराने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा को भी दुरुस्त किया। उन्होंने जिले में स्वच्छता मिशन को तरजीह दी, जिससे साहेबगंज की दो नगरपालिकाएं साहेबगंज और राजमहल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 'स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड' 2018 में सफल रहीं। इतना ही नहीं, डीसी संदीप सिंह के नेतृत्व में साहिबगंज को स्वच्छ गंगा शहर भी घोषित किया गया। यह जिला बदलाव के लिहाज से देश मे दूसरे नंबर पर रहा और जनवरी 2019 में नीति आयोग की ओर से "चैम्पियंस ऑफ चेंज अवॉर्ड" से नवाजा गया। जुलाई 2019 में संदीप सिंह को रामगढ़ जिले का डीसी बनाया गया। जहाँ उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण पर तेजी से कार्य शुरू करवाया। इनके द्वारा गढ़ा गया आंगनबाड़ी का रामगढ़ मॉडल राज्य के लिए रोल मॉडल है। कोविड-19 के संकट के समय संदीप सिंह ने महाराष्ट्र में फंसे रामगढ़ के मजदूरों के लिए तमाम सुविधाओं को मुहैया करवाया, जो सुर्खियों में रहा। आम लोगों तक प्रशासन की सहज उपलब्धता इनकी कार्यशैली का फ़ोकस रहा है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर रामगढ़ के जिलाधिकारी संदीप सिंह 'आईकॉन' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

उज्ज्वल

इच्छाशक्ति से संपन्न अधिकारी

अभिषेक कुमार तिवारी

टेक्नोक्रेट से आईएएस बनने वाले, प्रतिभा के धनी अभिषेक कुमार तिवारी की पहचान गंभीरता के साथ काम करने वाले जिलाधिकारी की है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कलेक्टर अभिषेक कुमार आम लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कला में माहिर माने जाते हैं। बिहार के आरा के रहने वाले अभिषेक कुमार तिवारी का जन्म 19 अप्रैल 1984 को हुआ। कुशाग्र छात्र रहे अभिषेक ने सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी से सीनियर सेकेंड्री की परीक्षा अव्वल नंबरों से पास करने के बाद उन्होंने 2002 -2006 बैच में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया।

उन्होंने बतौर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनर, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में नोएडा व बंगलुरु में नौकरी भी की। सब कुछ बेहतरीन तरीके चल रहा था। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि इस नौकरी से उनकी क्या पहचान होगी? यह सोच कर प्रशासनिक सेवा द्वारा आम लोगों के लिए बेहतर करने की मंशा के साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार में ही वे यूपीएससी 2012 बैच में बेहतर रैंकिंग से कम्पीट कर गए और उन्हें पश्चिम बंगाल कैडर मिला। जुलाई 2013 में अभिषेक तिवारी को कूच बिहार का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। एक साल बाद यानी सितंबर 2014 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बतौर एसडीएम ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार को तरजीह दी और नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों की समस्या के समाधान के मद्देनजर लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। 2016 में उनका ट्रांसफर ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर सीएम ऑफिस में हुआ। जून 2018 में उन्हें हावड़ा में का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया।

जून 2019 में अभिषेक तिवारी को जलपाईगुड़ी जिले का कलेक्टर बनाया गया। जिले की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने गरीब, मजदूर की आर्थिक मजबूती के लिए मनरेगा को बढ़ावा दे कर उसमें गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित की। मजदूरी का पैसा सीधे मजदूरों के अकाउंट में जाए, इस पर उन्होंने खासा ध्यान दिया। अभिषेक तिवारी ने जिले में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को जोड़ने काम व्यापक स्तर पर करवाया, ताकि गरीबों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने जिले में विकास के लेखाजोखा को दुरुस्त करने के लिए हर महीने रिपोर्ट लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की। ईमानदारी को अपना दायित्व मानने वाले इस टेक्नोक्रेट का प्रयास गरीबों मजदूरों को एक उज्जवल भविष्य की संभावना देना माना जाता है। कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों की आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें मनरेगा से जोड़ रहे हैं, साथ ही जिले में कोरोना को रोकने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी अभिषेक तिवारी 'उज्ज्वल' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

जवाबदेह

जवाबदेही का निर्वहन करने वाले

पल्लव गोपाल झा

सूझ-बूझ के साथ निर्भीकता से कर्तव्यों का निर्वहन करने और जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से पल्लव गोपाल झा असम के सबसे लोकप्रिय आईएएस अधिकारियों में शामिल हैं। समय के पाबंद पल्लव झा वर्तमान में डिब्रूगढ़ के उपायुक्त हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का गृह जिला है। ऐसे में वहाँ की नियुक्ति उनकी जवाबदेही लेने की क्षमता को स्वतः बयान करती है। पल्लव गोपाल झा के पिता डॉ. यू. जी. झा रिटायर्ड प्रोफेसर और माँ रिटायर्ड लैक्चरर हैं। 14 जुलाई 1985 को झारखंड के देवघर में उनका जन्म हुआ।

शुरुआती पढ़ाई सेंट फ्रांसिस स्कूल, देवघर में हुई। 12वीं उन्होंने देवघर के प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कालेजों में शुमार सेंट स्टीफेंस से फर्स्ट डिवीजन हासिल कर केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया। पल्लव गोपाल झा 2012 बैच में आईएएस चयनित हुए और उन्हें असम-मेघालय कैडर मिला। पल्लव गोपाल झा बतौर प्रशिक्षु असम में कुछ पदों पर रहे। इसी दौरान राज्य में पांच नये जिले बनाये गये और वे इनमें एक विश्वनाथ के पहले डिप्टी कमिश्नर बनाये गये। 2014 में जिले में जनजातीय हिसा और उग्रवादियों के हमले पर पल्लव गोपाल ने बड़ी सख्ती से काबू पाया, और उनकी पहचान एक निर्भीक आईएएस के तौर पर होने लगी। उन्होंने वहाँ लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने, ई-गर्वनेंस को बेहतर तरीके से लागू करवाने के अलावा जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कई अन्य कार्य किये। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व में जिला विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड प्राप्त किया।

वर्ष 2016 में पल्लव गोपाल झा को मजौली जिले का डीसी बनाया गया, जहाँ आयी बाढ़ के समय उनके राहत और बचाव के लिए किये गये कार्यों की चर्चा आज भी की जाती है। वर्ष 2018 में उनका ट्रांसफर शिवसागर जिले में बतौर डीसी किया गया, जहाँ नागरिकता संशोधन बिल के बड़े विरोध प्रदर्शन को उन्होंने प्रशासनिक सूझबूझ के साथ नियंत्रित किया। अक्टूबर 2019 में पल्लव गोपाल झा डिब्रूगढ़ जिले के उपायुक्त बनाये गये। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते जवाबदेही बड़ी थी, लेकिन नौ महीने से भी कम समय में वहाँ अपना प्रशासनिक कौशल प्रदर्शित कर लोकप्रिय जिलाधिकारियों में शामिल हुए। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और वेस्ट मैनेजमेंट आदि पर प्रभावी कार्य किया। परिणाम ये हुआ कि उनके नेतृत्व में डिब्रूगढ़ जिले ने राज्य सरकार से " पोषण अभियान अवॉर्ड", "स्वच्छता ही सेवा-2019 अवॉर्ड" में श्रेष्ठ जिले का सम्मान प्राप्त किया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2020 में उन्हें जल शक्ति मंत्रालय, भरत सरकार से सम्मान प्राप्त हुआ। पल्लव गोपाल झा कोरोना संक्रमण के दौर में भी डिब्रूगढ़ में काफी बेहतर काम कर रहे हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर डिब्रूगढ़ के जिलाधिकारी पल्लव गोपाल झा 'जवाबदेह' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

इरादे

मजबूत इरादों और लगन से बने लोकप्रिय जिलाधिकारी डी. अमॉय कुमार

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के जिलाधिकारी डी अमॉय कुमार शांत स्वभाव और गंभीर छवि के अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा शुरू से उनकी पहली पसंद थी क्योंकि उनके जीवन में सेवा का अहम स्थान है। उन्होंने अपने साहसिक कदमों से जो लोकप्रियता हासिल की है वो कम ही अधिकारियों को प्राप्त है।

मध्यम वर्गीय परिवार में अमॉय कुमार का जन्म 17 नवंबर 1981 को हुआ। 2007 में स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चुने गये। उनके लगन और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए किए काम को देखते हुए मात्र छह वर्षों की सेवा के बाद वर्ष 2013 में उन्हें केंद्र की प्रशासनिक सेवा में प्रमोट कर दिया गया। तेलंगाना में रहते हुए डी अमॉय कुमार को सबसे पहले अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने काफी कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किए। इसके बाद उनका तबादला रेवन्यू डिपार्टमेंट में हुआ और इस कार्यकाल में उन्होंने तेलंगाना के लिए लैंड रेवन्यू के क्षेत्र में जबरदस्त कार्य किया। फिर वे कई जिलों के जिलाधिकारी रहे जिनमें जयशंकर भूपलपल्ली और भद्राद्री कोठागुडेम प्रमुख थे। दोनों ही जिलों में अपने बेहतरीन कार्यों के कारण उन्होंने खासी लोकप्रियता बटोरी।

दिसंबर 2018 में डी अमॉय कुमार को सूर्यापेट में कलेक्टर बनाया गया। उन्होंने इस जिले में वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट प्रोग्राम को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया। जिले में 'पल्ले प्रगति' के कार्यों में तेजी लायी गयी। पेड़ों की कटाई को रोकने और संरक्षण के लिए तेलंगाना सरकार ने 'कू हरित हरम' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस योजना को डी अमॉय कुमार ने चुनौती के तौर पर लिया और जिले में पेड़ लगाने को प्रश्रय दिया। 'पल्ले प्रगति' और 'कू हरित हरम' योजना के कार्यान्वयन में सूर्यापेट को तेलंगाना के सभी जिलों में पहला स्थान मिला। जनवरी 2020 में रंगारेड्डी में बतौर जिलाधिकारी उन्होंने पदभार ग्रहण किया। यहां ज्वाइन करने के साथ जिले के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन प्रोग्राम को बेहतर किया गया। रंगारेड्डी जिले में भी डी अमॉय कुमार ने अपनी प्रिय योजनाओं 'पल्ले प्रगति' और 'कू हरित हरम' पर जबरदस्त ढंग से कार्य किया क्योंकि इस क्षेत्र के लिए हरियाली ना होना बड़ी समस्या है। इन सब के बीच कोरोना के आ जाने से जिलाधिकारी डी अमॉय कुमार की जवाबदेही काफी बढ़ गयी है। रंगारेड्डी जिले में जरूरी चीजों की कालाबाजारी और दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित किया और शिकायत मिलने पर संकट के घड़ी में घोखाधड़ी, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और मजबूत मनोबल से लोगों में विश्वास जगाने का कार्य किया है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर रंगारेड्डी के जिलाधिकारी अमॉय कुमार 'इरादे' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

प्रोग्रेसिव
★★★★★

विकास की परिभाषा गढ़ते

निशांत कुमार यादव

निशांत यादव का जन्म 13 मई 1990 को राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में हुआ। उनके पिता प्रिंसिपल और मां टीचर हैं।आईआईटी दिल्ली से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में एक साल बतौर बिजनेस एनालिस्ट काम करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया और वर्ष 2013 में आईएएस बनने में सफल रहे। पहली बार बतौर एसडीएम हरियाणा के सोनीपत में नियुक्ति हुई। जहाँ वे अपनी निष्पक्ष व कड़क छवि के लिये मशहूर रहे। बाद में करनाल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तौर पर स्वच्छता मिशन बेहतर कार्य किया, जिसके कारण करनाल ग्रामीण स्वच्छता के मामले में पूरे देश में सातवें स्थान पर रहा। इस दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण और सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया, जिसकी काफी सराहना हुई।

प्रशासनिक योग्यताओं को देखते हुए निशांत यादव को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने यहाँ निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा करावा कर अपने दायित्व का बेहतर निर्वहन किया। राज्य सरकार द्वारा उनकी क्षमता और प्रोग्रेसिव सोच को देखते हुए उन्हे करनाल का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। करनाल के उपायुक्त का पद संभालने के बाद निशांत यादव ने वहाँ स्मार्ट सिटी, फोर लेन , करनाल शुगर मिल का नवीनीकरण के साथ ही बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए ऑनलाइन बाल संगम पोर्टल की शुरुआत की। कोरोना संकट में उनके द्वारा दायित्वों को बेहतर तरीके से निभाने का जज्बा उनके हौसले की गवाही देता है। एडप्ट ए फैमली कांसेप्ट की शुरुआत, 600 बेड के आइसोलेशन बार्ड, प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की व्यवस्था आदि से इनके प्रशासनिक उत्कृष्टता को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। दरअसल जमीन से जुड़े लोगों के लिए काम करने की इच्छा शक्ति से निशांत कुमार यादव ने आम-जन को प्रशासन से जोड़ने में अहम कामयाबी हासिल की है ।

FAME INDIA

निशांत यादव एक ऐसे रुतबेदार कलेक्टर हैं जिन्हें सामाजिक अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के प्रति सख्त, और आम जनता के प्रति नर्म रवैये के कारण पहचाना जाता है। कठिन समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का बेहतरीन परिचय दे कर देशभर में अपनी अलग पहचान पायी है । कोरोना की जंग में समाजिक सहभागिता से निशांत यादव द्वारा जिले में शुरू किए गए "एडाप्ट ए फैमिली" कार्यक्रम में लोगो ने हजारों दैनिक कार्य करने वाले परिवार को गोद लिया, जिसकी सराहना केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने भी की और देश भर में इस कार्यक्रम को रोल मॉडल के तौर पर लिया गया ।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर करनाल के जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव 'प्रोग्रेसिव' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

माहिर

संकट में भी हौसला रखने के माहिर शशांका कोंडुरू

प्रशासनिक सेवा को जरूरतमंदों की सेवा का जरिया मानने वाले शशांका कोंडुरु करीमनगर के लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं। उन्हें विकासवादी सोच का ऑफिसर माना जाता है और सरकारी स्कीमों के सफल इंप्लिमेंटेशन के कारण प्रदेश सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों का भी भरोसा हासिल है। हैदराबाद में 25 मई 1985 को जन्मे शशांका कोंडुरु के पिता के.वेंकटैया आईडीपीएल में सुपरवाइजर और माता एम संयुक्ता गृहिणी रही हैं। उनका परिवार नालगोंडा के पैतृक गांव पेड्डा पाजिसाला को छोड़कर हैदराबाद आ गया था।

शशांका कोंडुरू की पढ़ाई हैदराबाद में हुई। उन्होंने सेंट अन्ना कॉलेज से बीए साइकोलॉजी और एमए हैदराबाद यूनिवर्सिटी से करने के बाद एसवी यूनिवर्सिटी तिरुपति से पीएचडी भी की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी शुरू की, लेकिन फिर प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया। उन्होंने वर्ष 2012 में यूपीएससी की परीक्षा दी तो प्रिलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाये, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले साल जब पूरी तैयारी से मैदान में उतरे तो देश भर में16 वीं और आंध्र प्रदेश के प्रथम रैंक हासिल कर आंध्रप्रदेश कैडर लिया। ट्रेनिंग के बाद उन्हें दिसंबर 2014 में करीमनगर के जगतियल ताल्लुके का सब-कलेक्टर बनाया गया। इसके बाद कुछ महीने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी रहे। दिसंबर 2016 में उन्हें करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बनाया गया जहां वे करीब 22 महीने रहे। कॉरपोरेशन के तमाम व्यवस्था को दुरुस्त किया और लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया।

सितंबर 2018 में शशांका को जिला जोगुलांबा-गडवाल का कलेक्टर बनाया गया जहां उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए नयी पहल की। वे खुद स्कूलों में क्लास लेने गये और दसवीं के छात्रों के लिए 'भविता' नाम से सोशल स्टडीज में सतत, विकास और समानता की पढ़ाई शुरू करवायी। ये प्रोग्राम केटी डोडी मॉडल में शुरू की गयी। इतना ही नहीं छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी डायट भी मिले इसकी व्यवस्था भी करवायी। आम लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विस मिले उसके लिए भी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए शशांका कोंडुरू दिसंबर 2019 में करीमनगर का जिलाधिकारी बनाया गया। उन्होंने करीमनगर में आम लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ पेयजल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इस बीच कोरोना आ धमका और इस वैश्विक महामारी से बचाने के लिए उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस पर जोर दिया। शशांका कोंडुरू ने केंद्र और बफर इलाकों की निशानदेही कर रैपिड हेल्थ सर्वे तथा साफ-सफाई का विशेष अभियान शुरुआत करवाया। करीमनगर शहर में घर -घर जाकर सर्वे किया गया। वे समाज के बड़े तबके तक पहुंचे और उन्हें सरकार की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर करीमनगर के जिलाधिकारी शशांका कोंडुरु 'माहिर' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

सुधारवादी

सुधारवादी कार्यों से बनायी पहचान

नैंसी सहाय

रांची के योगदा कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर प्रकाश सहाय और स्कूल टीचर राज लक्ष्मी के घर 05 अप्रैल 1989 को नैन्सी सहाय का जन्म हुआ। चुनौतियों को आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता से जीतने का हौसला रखने वाली रांची की नैन्सी सहाय का सपना तो इंजीनियर बनने का था, लेकिन कुछ समय तक कार्य करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया और आज एक सुधारवादी आईएएस अधिकारी के तौर पर देश में पहचान रखती हैं। नैन्सी वर्तमान में झारखंड के देवघर की जिला उपायुक्त हैं और जिले को विकास की राह पर तेजी से अग्रसर किया है।

रांची के प्रसिद्ध स्कूल लोरेटो कॉन्वेंट से 10वीं व डीएवी श्यामली से 12वीं करने के बाद नैन्सी सहाय ने बीआईटी, मेसरा से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2011 में गुरुग्राम में कुछ महीनों के लिए बतौर साफ्टवेयर इंजीनियर जॉब भी किया, परन्तु फिर उन्होंने माँ-पापा की प्रेरणा से यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने का निर्णय किया। 2014 बैच में वे 36 वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनीं, उन्हें होम कैडर झारखंड मिला। उनकी शादी 2014 बैच के ही आईएएस वरुण रंजन से हुई जो फिलहाल साहिबगंज में डीसी हैं। नैन्सी की पहली पोस्टिंग झारखंड के मेदिनीपुर का एसडीओ के तौर पर हुई, जहाँ उन्होंने परीक्षा में कदाचार के मामलों और प्रश्न पत्र लीक करनेवाले गैंग के खिलाफ जबरदस्त कारवाई की। उन्होंने मेदिनीपुरम में स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी से एक मिशन बना दिया। जून 2017 में उन्हें साहिबगंज का डीडीसी बनाया गया। यहां उन्होंने वन क्षेत्र में पाये जाने वाले वनोत्पाद को संरक्षित करने, बांस, चिरैता और दूसरी जड़ी-बूटियों के अलावा मधु मक्खी पालन से भी लोगों की आय बढ़ाने और ज्ञानज्योति कार्यक्रम द्वारा जिले की शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करवाने पर विशेष ध्यान दिया।

अगस्त 2019 में नैन्सी सहाय को बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। बैद्यनाथ धाम के नाम से मशहूर जिले देवघर की वे पहली महिला उपायुक्त बनायी गयी हैं। इस शहर के धार्मिक महत्व के अनुरूप उन्होंने जिले के विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर बतौर जिलाधिकारी अपनी लोकप्रिय छवि स्थापित की। कोरोना काल में भी उनके प्राशसनिक कार्य कौशल की सराहना हो रही है। जागरूकता, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के साथ ही उन्होंने जिले में जरूरी सामानों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था और कालाबाजारी पर रोक लगाने में सफलता पायी। वे सही समय पर सही तरीके से काम करने को सफलता की कुंजी मानती हैं। कोमल हदय नैन्सी गरीबों और पिछड़ों के दुख-दर्द को गहराई से महसूस करती हैं और अपनी भावनाओं को कविताओं में भी व्यक्त करती हैं।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिंदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर देवघर की जिलाधिकारी नैन्सी सहाय 'सुधारवादी' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

युवा ★★★★★

तेज-तर्रार कार्यशैली से बनायी पहचान

शशांक शुभंकर

समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की मंशा रखने वाले तेज-तर्रार और जवाबदेह अधिकारी के तौर पर फेमस शशांक शुभंकर वर्तमान में बिहार के समस्तीपुर के जिलाधिकारी हैं। वे समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने और उसके मुताबिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। शशांक का जन्म 11 सितंबर 1991 को हुआ। उनका परिवार कई पीढ़ियों से प्रशासन में है। दादा स्व. सिद्धेश्वरी नाथ सम्मिलित बिहार-झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी थे और पिता अनिल कुमार सिन्हा झारखंड सरकार में अधिकारी हैं।

शशांक शुभंकर शुरू से बेहद लगनशील और पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। वे डीएवी पब्लिक स्कूल रांची के स्टूडेंट थे और बचपन में ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। छठी कक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर हुए साइंस ओलिंपियाड में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। जब नयी दिल्ली से अवॉर्ड लेकर वापस लौटे और पत्रकारों ने भविष्य के विषय में सवाल पूछा तो नन्हे शशांक ने उत्तर दिया कि उसे आईएएस बनना है। वे 10वीं और 12वीं मे बैच टॉपर भी रहे। वीआईटी, वेल्लोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल के साथ बीटेक करने के बाद वे सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गये। 2014 बैच में कामयाबी मिली और वे बिहार कैडर के आईएएस बने। शशांक शुभंकर की पत्नी उदिता सिंह भी बिहार कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

अगस्त 2015 में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में शशांक असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाये गये। बाद में उन्हे डीडीसी आरा बनाया गया। आरा में डीडीसी रहते हुए उन्होंने सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया और काफी सुर्खियां बटोरी। शशांक शुभंकर को अगस्त 2019 में समस्तीपुर के जिलाधिकारी का दायित्व दिया गया। उन्होंने समस्तीपुर में विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने को प्राथमिकता दी। आम लोगों के लिए सहजता से उपलब्ध होना और उनकी समस्या के त्वरित निदान का प्रयास उन्हे लोकप्रिय जिलाधिकारी के तौर पर स्थापित करता है। शशांक शुभंकर समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि जनसरोकार के कार्य में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जिले में गन्ना किसानों के बकाये के जल्द भुगतान को सुनिश्चित करने को लेकर पहल की। समस्तीपुर में खुले में शौच पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के कारण वे लोगों के चहेते बन गये हैं। जिला शिशु गृह में बच्चों के स्पेशल केयर की व्यवस्था करवाने के शशांक शुभंकर के प्रयास को बेहद सराहनीय माना गया। उन्होंने जिले में कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए कई सरहानीय कदम उठाये, जिनमें आइसोलेशन, टेस्टिंग और क्वारंटाइन सेंटर की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से बराबर जानकारी लेना, जागरुकता पर विशेष ध्यान देना साथ ही हमेशा आम लोगों की बेहतरी के लिए 24X7 मुस्तैद रहना इस युवा जिलाधिकारी की खासियत है।

फेम इंडिया - एशिया पोस्ट के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी 2020 के सर्वे में

लोकप्रियता	✓	कार्यशैली	✓
सक्रियता	✓	छवि	✓
शानदार गवर्नेंस	✓	फैसले लेने की क्षमता	✓
दूरदर्शिता	✓	जनता से संवाद	✓
उत्कृष्ट सोच	✓	व्यवहार कुशलता	✓

इन दस बिदुओं पर किये गए आंकलन के आधार पर समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर 'युवा' श्रेणी में प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- देशभर के प्रबुद्ध लोगों से स्टेक होल्ड सर्वे पर आधारित

आस्था

देश के हिन्दू तीर्थ स्थलों में बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय के निकट मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र महादेव का अलग ही महत्व है। ये महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह अपने आप में दुनिया में अनोखी जगह है, जहां एक साथ शिव के विभिन्न रूपों 11 शिवलिंगों का दर्शन व पूजन का अवसर मिलता है। यहां शिव 11 रूपों महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम देवदेवा, भदोद्भव एवं कपालिश्च के दर्शन का सौभाग्य शिव भक्तों को विशेष तौर पर मिलता है।

मधुबनी में स्थापित है एकादश रुद्र महादेव का दुर्लभ मंदिर

इसके अलावा इस एकादश रुद्र मंदिर परिसर में विष्णु के विभिन्न अवतारों, श्री विद्या यंत्र, विष्णुपद गया क्षेत्र, महाकाल, महाकाली, गणेश सरस्वती आदि साथ ही आम एवं महुआ का आलिंगन-बद्ध वृक्ष, भगवान शिव, पार्वती, महा-लक्ष्मी, महा-सरस्वती यंत्र, विष्णु-पादुका आदि के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है।

इस परिसर स्थित पीपल वृक्ष का भी तांत्रिक महत्तम अलग ही है। कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से भूत प्रेत के प्रभाव से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। वहीं श्री विद्या यंत्र के दर्शन व पूजन से लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है।

सोमवार के दिन यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, इस दिन यहां रुद्राभिषेक एवं षोडषोपचार पूजन करते हैं तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। पंडित जी बताते हैं कि यहां एक ही शक्ति-वेदी पर स्थापित शिव के सभी एकादश रुद्र लिंग रूपों में 10 मई से 21 मई 2000 ई. के बीच विभिन्न तरह की आकृतियां उभर आयीं।

1 महादेव - विगत 30 जुलाई 2001 को अर्द्ध-नारीश्वर का रूप प्रकट हुआ है। कामाख्या माई का ये भव्य रूप है। पांचवें सोमवारी के दिन गणेश जी गर्भ में प्रकट हुए। शिवलिंग पर ये रूप स्पष्ट नजर आती है।

2 शिव - प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं ही शिव हूं। इस लिंग में सिंहासन का चित्र उभरा है, जो प्रभु श्री राम का सिंहासन दर्शाता है।

3 रुद्र - भय को हराने वाले इस लिंग में बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे है बड़ा ही अद्भुत चित्र प्रकट हुआ है।

4 शंकर - गीता के दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही शंकर हूं। इस लिंग में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बांसुरी और बाजूबंध स्पष्ट दृष्टिकोण होता है।

5 नील लोहित- जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनका नाम नील लोहित पड़ गया था। इस लिंग में सांप एवं ॐ का अक्षर प्रकट हुआ है।

6 ईशान - हिमालय पर निवास करने वाले महादेव जिसे केदारनाथ कहते हैं विगत नौ जुलाई 2001 सावन के पहले सोमवार को राजराजेश्वरी का रूप प्रकट हुआ।

7 विजय - इस शिवलिंग में छवि बन रही है जिस कारण आकृति अस्पष्ट है।

8 भीम - महादेव का एक रूप भी है। इस शिवलिंग में गदा की छवि उभर कर सामने आयी है। गदा का डंडा अभी धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है।

9 देवादेव - ये लिंग सूर्य का रूप है। इस शिवलिंग में गदा के नीचे दो भागों से सूर्य की किरणें फूटकर शीर्ष में मिल रही है।

10 भवोद्भव - इस लिंग में उमा शंकर की आकृति प्रकट हुई है। दोनों आकृतियां धीरे-धीरे बढ़ रही है।

11 कपालिश्च- महादेव का एक रूप बजरंगबली है। बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिये संभवतः इस लिंग में कोई चित्र नहीं उभर रहा है। किसी दिन ये शिवलिंग अपने आप पूरा लाल हो जायेगा।

> कांची पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल व अधीक्षण पुरातत्व-विद डॉ। फणीकांत मिश्र आदि आये तो यहां शिव के एकादश रुद्र का अलौकिक रूप देख भाव विह्वल हो गये। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय पूजन व तीर्थ स्थल है।

बाबा जी का कहना है कि सभी शिव भक्तों को मात्र एक बार आकर इन शिवलिंगों उभरी हुई आकृतियों को देखे तो पता लगेगा कि ऐसे शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं हैं

गौरतलब है कि प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने 1953 ई. में यहां शिव मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में स्थापित सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं जिनका प्रत्येक सोमवार शाम को दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत, चंदन आदि से स्नान होता है। श्रृंगार के लिये विशेष तौर पर कोलकाता से कमल के फूल मंगाये जाते हैं। प्रधान पुजारी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने नहीं गया नहीं जा पाते उनके लिये यहां गया क्षेत्र बना है जहां पिण्डदान कर मुक्ति पायी जाती है।

MEDICINES OR DOUBLE IMMUNITY?

THE CHOICE IS YOURS.

THIS WINTER GIVE YOUR CHILD THE DOUBLE IMMUNITY OF DABUR CHYAWANPRASH.

Dabur Chyawanprash is a formulation of Ashwagandha, Guduchi, Amla and 40 other herbs that help boost immunity and provide protection from illnesses during winters.

DABUR AROGYA: CALL OR WRITE
8/3, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI - 110002
E-Mail: daburcares@feedback.dabur
TOLL FREE: 1800-103-1644
FREE DOCTOR CONSULTATION

आउट ऑफ बॉक्स फैसला करने वाले अधिकारियों की जरूरत है देश को

मैंने हमेशा उन अधिकारियों का सम्मान किया है जो जो आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लेते हैं। वैसे अधिकारियों का कोई सम्मान नहीं करता जो कोई फैसला नहीं लेते। मैंने कई बार कहा है कि कोई निर्णय न लेना भ्रष्टाचार से भी बड़ा अपराध है। अगर जिलाधिकारी अपने जिले के लोगों के लिये कोई अच्छा और बोल्ड निर्णय सिर्फ इस आशंका से नहीं लेते कि भविष्य में उसकी विफलता के लिये उन्हें दोषी माना जा सकता है तो ऐसा करके वो उसकी सफलता की संभावना पर भी रोक लगा रहे हैं। मेरे एक मित्र, जो एक सफल आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है ने एक आसान फॉर्मूला बताया। अगर कोई लोक कल्याणकारी निर्णय लेना है तो पूरी पंचायत बिठा कर लें। सारे संबंधित विभागों के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, बैंक मैनेजर आदि जितने संबंधित लोग हों सबको अपने निर्णय में उनसे हस्ताक्षर करवा कर शामिल कर लें। अगर कल कोई सवाल उठाता है तो आपके फैसले को इतने सारे लोगों की ताकत मिलेगी। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आउट ऑफ बॉक्स निर्णयों ने समाज की दिशा बदल कर रख दी है।

आज के अधिकारियों को एक और चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसे मैं जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक मानता हूँ। सर्विस हो, व्यापार हो या राजनीति, हर क्षेत्र में मानवीय संबंधों की महत्ता सबसे अधिक है। मैंने कभी भी किसी अधिकारी से मुलाकात करने में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और मुझे हमेशा इसका बहुत सुखद नतीजा मिला है। अगर आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं और अगर आपके सबॉर्डिनेट से रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। मेरे अधिकतर निर्णय जो बहुत सफल हुए हैं उनमें में उन सचिवों का बहुत योगदान है जो खुलकर कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं किस प्वॉइंट पर सही हूँ और किस प्वॉइंट पर गलत।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है सोशल और नैशनल कमिटमेंट। मेरी नजर में यह एक ऐसी आवश्यकता है जो हर अधिकारी में होनी चाहिये। अगर आप समाज और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख कर निर्णय लेंगे तो आपको सदैव सराहना मिलेगी। एक अधिकारी को जाति, धर्म, भाषा और लिंग के भेद से ऊपर उठ कर फैसला करना सीखना चाहिये। गांधी जी का वो वक्तव्य याद रखो जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला लेते समय समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद रखें और सोचें कि इससे उसे क्या लाभ मिल सकेगा। समाज के लिये कमिटमेंट बेहद आवश्यक है। हमारे बीच कई जिलाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पूरा देश गर्व के साथ देख रहा है।

अंग्रेजी में एक कहावत है, "इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे" यानी जहां चाह है वहां राह है। लेकिन अगर कुछ करने की चाहत ही नहीं है तो फिर केवल सर्वे, डिस्कशंस, सेमिनार्स, कमेटि, सब कमेटि आदि हैं। इच्छाशक्ति बहुत आवश्यक है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिये। मुझे लगता है कि समय कम है और देश में संसाधनों की कमी नहीं है। सभी ऑफिसर अगर तीव्र इच्छाशक्ति के साथ समाज और देश के लिये कार्य करने में जुट जायें तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं।

- नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग,
जल संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार

फेम इंडिया के बढ़ते कदम ...
सफलता के 8 वर्ष ....

सोच बदलें, समाज बदलेगा

सदस्यता फार्म

मैं फेम इंडिया की सदस्यता ले रहा / रही हूं

श्रीमती/ कुमारी/ श्री ....

पता: ....

.... राज्य ....

फोन (निवास) .... मोबाइल ....

ई-मेल ....

कृपया .... के नाम .... का डी डी

या चेक नं. ....

बैंक का नाम ....

चैक फेम इंडिया के नाम पर देय होगा

दिल्ली के बाहर से भेजे गए चेक में कृपया 30 रूपया अधिक भेजें

कृपया इस फार्म को भरकर डी डी या चेक के साथ हमें इस पते पर भेजें

फेम इंडिया

फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि. 762, F- 8, सेक्टर 50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)

फोन नं. 09711535422

ई मेल-ई मेल- info.fameindia.co

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	सब्सक्रिप्शन मूल्य	बचत
1 वर्ष	12	1200	1000	200
2 वर्ष	24	2400	2000	400
3 वर्ष	36	3600	3000	600

POWERFUL. AGILE.
INTELLIGENT.
THE ALL-NEW BMW 5 SERIES. BUSINESS ATHLETE.
M BB4102
Sheer
Driving Pleasure